सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh

RNI No :- DELHIN/2023/86499
DCP Licensing Number : F.2 (P-2) Press/2023

www.newsparivahan.com

परिवहन विशेष

वर्ष 02, अंक 237, नई दिल्ली । बुधवार, 06 नवम्बर 2024, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

जीवन में जिसने अपनी जीभ को संभालना सीख लिया, वो जीवन को भी संभाल लेगा, क्योंकि जीभ का स्वाद स्वास्थ्य खराब करता है और वाणी संबंध खराब कराती है।

03 "-'आप' सरकार की मुफ्त बस यात्रा योजना ने बनाया नया रिकॉर्ड
06 अदृश्य जंजीरें: डिजिटल युग में इंटरनेट की लत
08 "वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर पत्थरबाजी की बढ़ती घटनाएं चिंताजनक"

अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं परिवहन आयुक्त दिल्ली द्वारा जनता के वाहनों को जबरदस्ती उठवाकर अपने जिन प्रिय बाहरी राज्यों में पंजीकृत वाहन स्क्रैप डीलरों को सुपूर्द किया जा रहा है उसके प्रति विभाग में जमा हुई विशेष शिक़ायत

क्या अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं परिवहन आयुक्त दिल्ली को इस बात की जानकारी नहीं थी या जानते हुए भी इनको जनता के वाहन सुपूर्द करवाने के निर्देश जारी किए, सोचनीय बात

संजय बाटला

नई दिल्ली। आपकी जानकारी हेतु बता दे बाहरी राज्यों में पंजीकृत जिन वाहन स्क्रैप डीलरो को अतिरिक्त मुख्य सचिव एवम्‌ परिवहन आयुक्त के दिशा निर्देशों पर दिल्ली की जनता के वाहन सुपूर्द किए जा रहे हैं उनमें से कुछ ने पिछले साल परिवहन विभाग से जनता के प्राप्त किए हुए वाहनों के पैसे अब तक नहीं दिए और ना ही विभाग में जमा करवाएं हैं फिर भी उनको इस साल भी जनता के वाहनों को सुपूर्द किया जा रहा है।इनमें से 6 ऐसे वाहन स्क्रैप डीलर हैं जिन्होंने पिछले साल जो सरकारी वाहन नीलामी में बोली लगाकर स्क्रैप के लिए खरीदे थे उनके स्क्रैप के दस्तावेज़ जमा करने के लिए असफल रहे और उन्हें सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा सरकारी वाहनों की बोली के लिए ब्लैक लिस्टेड कर रखा है।इनमें से कुछ वाहन स्क्रैप डीलर दिल्ली से इतनी दूर क्षेत्र में पंजीकृत हैं जहां रोज के प्राप्त किए वाहन ले जाना असंभव है और उनके पास दिल्ली में कोई पंजीकृत वाहन संग्रह केन्द्र नहीं है। ऐसे में वह वाहन स्क्रैप डीलर कहा ले जाकर वाहन संग्रह कर रहे हैं या स्क्रैप कर रहे है।

इन्ही मुद्दों को लेकर के रवि नाम के किसी व्यक्ति ने विशेष परिवहन आयुक्त और उपायुक्त स्क्रैप के पास आज लिखित में एक शिक़ायत/सुझाव जमा किया है।जिसकी प्रति व्हाट्सएप के माध्यम से परिवहन विशेष को भी प्राप्त हुई और जो बाते के रवि द्वारा अपने इस पत्र में लिखी है उसके अनुसार जिन वाहन स्क्रैप डीलरो को अतिरिक्त मुख्य सचिव एवम्‌ परिवहन आयुक्त दिल्ली के दिशा निर्देशों पर जनता के वाहन सुपूर्द करवाए जा रहे हैं वह न्याय और क़ानून दोनों ही दृष्टि में गलत हैं पर दिल्ली के परिवहन विभाग आयुक्त साथ में अतिरिक्त मुख्य सचिव जो कहे, जो करे, जो करवाए वह ही न्यायिक बाकी सब बेकार

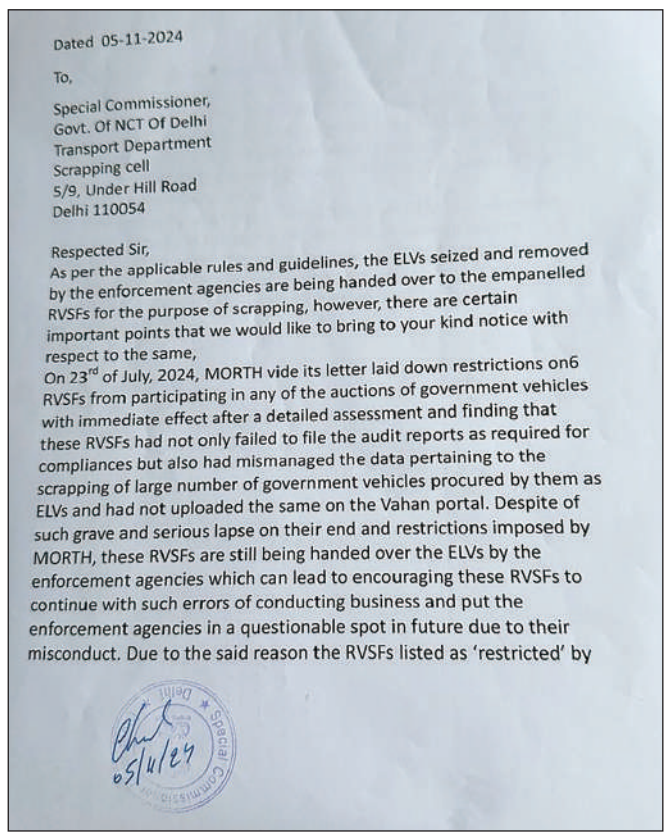

अब देखना यह होगा की सच्चाई सामने आने के बाद भी अतिरिक्त मुख्य सचिव एवम्‌ परिवहन आयुक्त दिल्ली इन सभी बाहरी राज्यों में पंजीकृत वाहन स्क्रैप डीलरो के खिलाफ कोई कार्यवाही के आदेश करते हैं या जनता के वाहनों को इन्हें सुपूर्द करवाते रहते हैं।

Dated 05-11-2024

To,

Special Commissioner,
Govt. Of NCT Of Delhi
Transport Department
Scrapping cell
5/9, Under Hill Road
Delhi 110054

Respected Sir,
As per the applicable rules and guidelines, the ELVs seized and removed by the enforcement agencies are being handed over to the empanelled RVSFs for the purpose of scrapping, however, there are certain important points that we would like to bring to your kind notice with respect to the same,
On 23rd of July, 2024, MORTH vide its letter laid down restrictions on6 RVSFs from participating in any of the auctions of government vehicles with immediate effect after a detailed assessment and finding that these RVSFs had not only failed to file the audit reports as required for compliances but also had mismanaged the data pertaining to the scrapping of large number of government vehicles procured by them as ELVs and had not uploaded the same on the Vahan portal. Despite of such grave and serious lapse on their end and restrictions imposed by MORTH, these RVSFs are still being handed over the ELVs by the enforcement agencies which can lead to encouraging these RVSFs to continue with such errors of conducting business and put the enforcement agencies in a questionable spot in future due to their misconduct. Due to the said reason the RVSFs listed as 'restricted' by

05/11/24

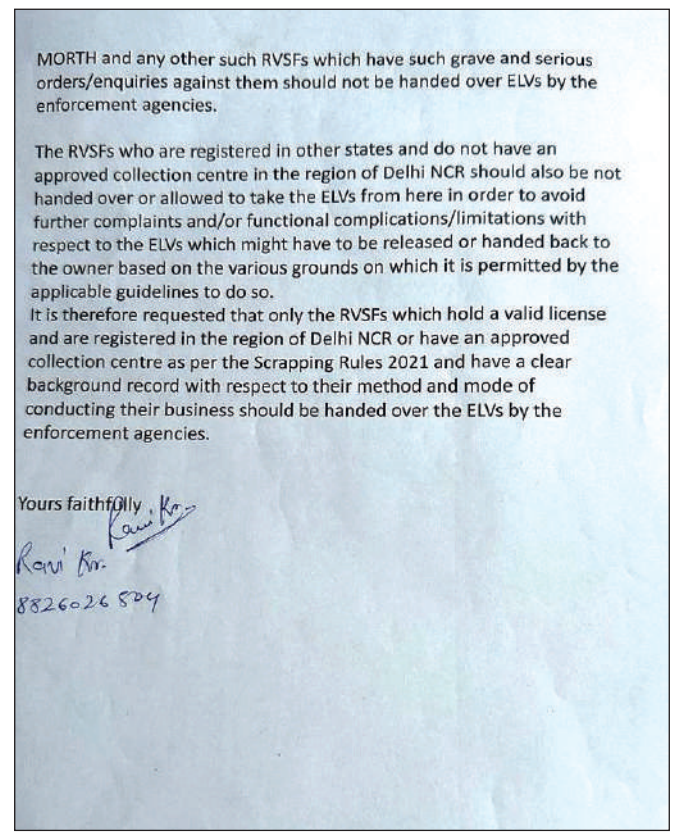

MORTH and any other such RVSFs which have such grave and serious orders/enquiries against them should not be handed over ELVs by the enforcement agencies.

The RVSFs who are registered in other states and do not have an approved collection centre in the region of Delhi NCR should also be not handed over or allowed to take the ELVs from here in order to avoid further complaints and/or functional complications/limitations with respect to the ELVs which might have to be released or handed back to the owner based on the various grounds on which it is permitted by the applicable guidelines to do so.
It is therefore requested that only the RVSFs which hold a valid license and are registered in the region of Delhi NCR or have an approved collection centre as per the Scrapping Rules 2021 and have a clear background record with respect to their method and mode of conducting their business should be handed over the ELVs by the enforcement agencies.

Yours faithfully
Ravi Kr.
8826026504

सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला- निजी संपत्तियों पर सरकार नहीं कर सकती कब्जा

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संविधान पीठ ने मंगलवार को निजी संपत्तियों पर सरकारी अधिकार को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में 8–1 के बहुमत से यह निर्णय लिया गया। अदालत ने स्पष्ट किया कि सभी निजी संपत्तियों को सामुदायिक संसाधनों के रूप में नहीं देखा जा सकता, जिन्हें राज्य सरकार आम भलाई के लिए अपने कब्जे में ले सके।

सभी निजी संपतियों पर सरकारी अधिकार नहीं :– सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि संविधान के अनुच्छेद 39 (बी) के तहत सभी निजी संपत्तियों को 'समुदाय के भौतिक संसाधनों' का हिस्सा नहीं माना जा सकता और न ही राज्य उन्हें 'सार्वजनिक भलाई' के नाम पर अपने अधिकार में ले सकता है। कोर्ट ने 1978 से संबंधित कई पुराने फैसलों को पलटते हुए कहा कि केवल कुछ संपत्तियां ही सामुदायिक भलाई के लिए उपयुक्त हो सकती हैं, लेकिन सभी संपत्तियों पर सरकारी अधिकार नहीं बनता।

विश्वस्त सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार वीरवार तक दिल्ली में ग्रेप 3 लागू कर दिया जाएगा

संजय बाटला

नई दिल्ली। दिल्ली में बढ़ते प्रदुषण को देखते हुए आज मंत्री गोपाल राय द्वारा बैठक बुलाई गई और निर्णायक फैसला लेते हुए ग्रेप 3 को लागू करने और उस पर सख्ती से पालन करवाने के लिए सभी विभागो को तैयार रहने के निर्देश जारी किए। इसके बाद यह स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है की 7 तारीख को छठ पूजा की छुट्टी के तुरंत बाद या उसी दिन ग्रेप 3 के आदेश लागू कर दिए जाएंगे।

जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है दिल्ली लगातार प्रदूषण के उच्च स्तर से जूझ रही है और एक दर्जन से अधिक स्टेशन हर बार "गंभीर" श्रेणी में आ रहे हैं। यह जानना जरूरी हो गया है की इतना प्रदूषण कैसे हो रहा हैं.

प्राप्त जानकारी के अनुसार सोमवार 4 नवंबर को, दिल्ली के वायु प्रदूषण का लगभग एक-चौथाई हिस्सा पराली जलाने से जुड़ा हुआ पाया गया और जो एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय चुनौती है.

दिवाली के बाद से ही दिल्ली में प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ने की खबरें आने लगी थी. इससे दिल्लीवासियों को कई प्रकार की स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. वायु गुणवत्ता सूचकांक बिगड़ने से आज दिल्ली का औसत एक्यूआई 384 रिकॉर्ड किया गया, जो 'बहुत खराब' श्रेणी में है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक, आनंद विहार इलाके में एक्यूआई 400 अंक को पार कर गया है, जो आज यानी 5 नवंबर को सुबह करीब 7 बजे 457 दर्ज किया गया, जो 'गंभीर' श्रेणी में आता है. इससे पहले सोमवार को भी यहां का एक्यूआई 350 के पार दर्ज किया गया था. वहीं, दिल्ली के जहांगीरपुरी में एक्यूआई 440 दर्ज किया गया है.

दिल्ली में गाड़ियों के धुएं के कारण 13.7 % प्रदूषण कहा जा रहा है। इसका मुख्य कारण ऑफिस जाने वाले लोगों के निजी वाहन बताए जा रहे है. दिल्ली और उसके आस-पास के इलाकों में, फैक्ट्री से निकलने वाले प्रदूषण का 3.4 प्रतिशत बताया गया है. वही, निर्माण गतिविधियों के कारण लगभग 2% फीसदी और सड़क की धूल से दिल्ली में कुल प्रदूषण का 1% हिस्सा ही सिर्फ बताया जा रहा है. शहर में लगातार चिंता का विषय बने रहने वाले कचरे को जलाने से प्रदूषण में 1.3% से अधिक की वृद्धि हुई है.

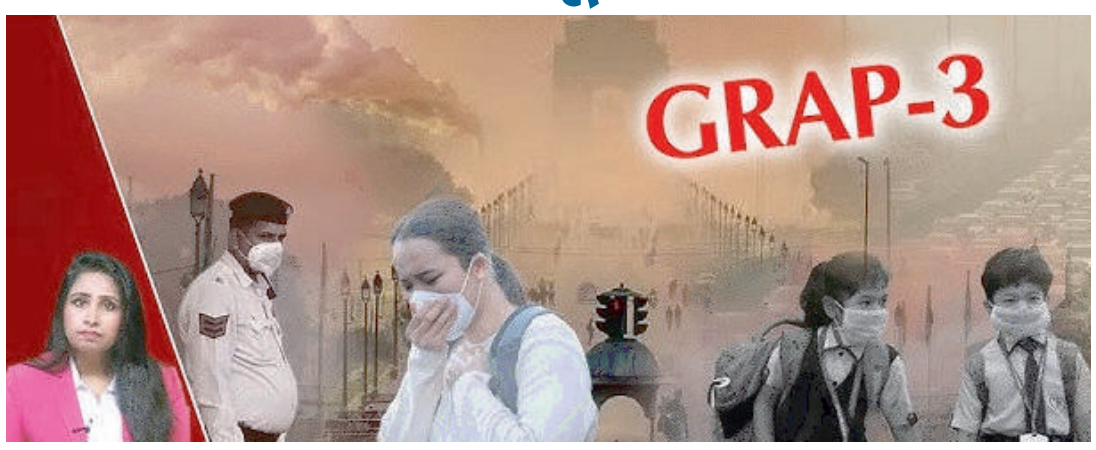

आपकी जानकारी हेतु बता दे क्या होता है ग्रेप?:- ग्रेप का मतलब ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान है. यह सरकार की एक योजना है, जिसे दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के खिलाफ बनाया गया है. इस प्लान के जरिए प्रदूषण को कंट्रोल किया जाता है. दरअसल, इसके कई चरण हैं और ये चरण भी बढ़ते प्रदूषण के साथ बढ़ते जाते हैं. जैसे जैसे चरण बढ़ते हैं, वैसे वैसे दिल्ली में पाबंदियां भी बढ़ती जाती हैं.

ग्रेप के 4 चरण रखे गए हैं:- जब दिल्ली में हवा 201 से 300 एक्यूआई तक खराब होती है तो पहला चरण लागू किया जाता है. इसके बाद अगर हवा ज्यादा खराब होती है और एक्यूआई 301 से 400 तक पहुंच जाता है तो इसका दूसरा चरण लागू हो जाता है. अगर हवा ज्यादा खराब हो जाए यानी एक्यूआई 400 से भी ज्यादा हो जाए तो तीसरा चरण लगता है. हालात ज्यादा खराब होने पर ग्रेप का चौथा लेवल लागू कर दिया जाता है. वायु प्रदूषण से कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं. इसी के आधार पर दिल्ली-एनसीआर में ग्रेप श्रेणी की पाबंदियां लगाई जाती हैं. आपको बता दें ग्रेप-2 लागू होने के बाद 5 प्रमुख पाबंदियां दिल्ली में दिवाली से पहले ही लागू कर दी जा चुकी हैं.

दिल्ली-एनसीआर में ग्रेप-2 के तहत जो पाबंदियां लागू है, वह हैः-

* डीजल जनरेटर चलने पर रोक लगेगी.
* प्राइवेट गाड़ियों के इस्तेमाल को कम करने के लिए पार्किंग फीस को बढ़ाया जाएगा.
* प्रतिदिन सड़कों पर मैकेनिकल /वैक्यूम स्वीपिंग और पानी का छिड़काव होगा.
* सीएनजी-इलेक्ट्रिक बसों और मेट्रो की सर्विस को बढ़ाया जाएगा.
* आर डब्ल्यू अपने सिक्योरिटी गार्ड को हीटर देंगी ताकि वे गर्माहट के लिए कूड़ा, लकड़ी या कोयला न जलाएं.
* नैचुरल गैस, बायो गैस, एलपीजी से चलने वाले जेनरेटर चल सकेंगे.
* 800 किलो वाट से अधिक क्षमता वाले जेनरेटर तभी चल सकेंगे जब वह रेट्रोफिटिंग करवाएंगे।

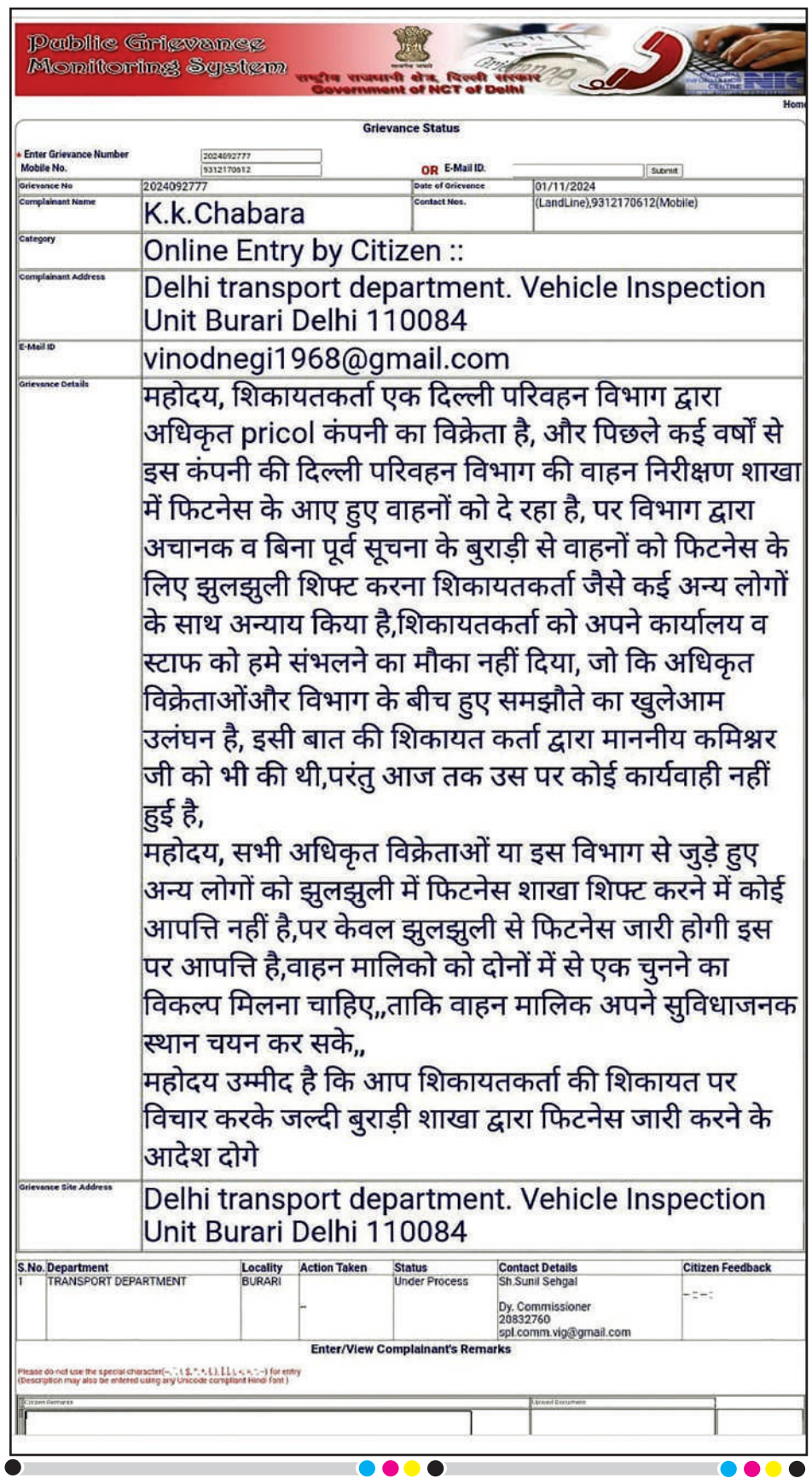

Public Grievance Monitoring System
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
Government of NCT of Delhi

Grievance Status

Enter Grievance Number: 2024092777
Mobile No.: 9312170612
OR E-Mail ID: Submit

Grievance No	2024092777	Date of Grievance	01/11/2024
Complainant Name	K.k.Chabara	Contact Nos.	(LandLine),9312170612(Mobile)
Category	Online Entry by Citizen ::		
Complainant Address	Delhi transport department. Vehicle Inspection Unit Burari Delhi 110084		
E-Mail ID	vinodnegi1968@gmail.com		
Grievance Details	महोदय, शिकायतकर्ता एक दिल्ली परिवहन विभाग द्वारा अधिकृत pricol कंपनी का विक्रेता है, और पिछले कई वर्षों से इस कंपनी की दिल्ली परिवहन विभाग की वाहन निरीक्षण शाखा में फिटनेस के आए हुए वाहनों को दे रहा है, पर विभाग द्वारा अचानक व बिना पूर्व सूचना के बुराड़ी से वाहनों को फिटनेस के लिए झुलझुली शिफ्ट करना शिकायतकर्ता जैसे कई अन्य लोगों के साथ अन्याय किया है,शिकायतकर्ता को अपने कार्यालय व स्टाफ को हमे संभलने का मौका नहीं दिया, जो कि अधिकृत विक्रेताओंऔर विभाग के बीच हुए समझौते का खुलेआम उलंघन है, इसी बात की शिकायत कर्ता द्वारा माननीय कमिश्नर जी को भी की थी,परंतु आज तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है, महोदय, सभी अधिकृत विक्रेताओं या इस विभाग से जुड़े हुए अन्य लोगों को झुलझुली में फिटनेस शाखा शिफ्ट करने में कोई आपत्ति नहीं है,पर केवल झुलझुली से फिटनेस जारी होगी इस पर आपत्ति है,वाहन मालिको को दोनों में से एक चुनने का विकल्प मिलना चाहिए,,ताकि वाहन मालिक अपने सुविधाजनक स्थान चयन कर सके,, महोदय उम्मीद है कि आप शिकायतकर्ता की शिकायत पर विचार करके जल्दी बुराड़ी शाखा द्वारा फिटनेस जारी करने के आदेश दोगे		
Grievance Site Address	Delhi transport department. Vehicle Inspection Unit Burari Delhi 110084		

S.No.	Department	Locality	Action Taken	Status	Contact Details	Citizen Feedback
1	TRANSPORT DEPARTMENT	BURARI	--	Under Process	Sh.Sunil Sehgal Dy. Commissioner 20832760 spl.comm.vig@gmail.com	

Enter/View Complainant's Remarks

छठ पूजा पर ग्रह-गोचर का बन रहा शुभ संयोग

ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास ने बताया कि छठ व्रती सात नवंबर को अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देंगी। इस दिन षष्ठी तिथि को छठी मैया का पूजन विधि-विधान के साथ होगा। सात नवंबर को धृति व रवियोग का संयोग बना रहेगा।

छठ महापर्व की नहाय-खाय के साथ शुरुआत हो चुकी है। चार दिनों तक चलने वाले इस पर्व के पहले दिन नहाय-खाय, दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन संध्या अर्घ्य और चौथे दिन उषा अर्घ्य देते हुए समापन होता है। छठ महापर्व सूर्य उपासना का सबसे बड़ा त्योहार होता है। पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर - जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास ने बताया कि लोक आस्था का महापर्व छठ पर्व नहाय खाय के साथ शुरू हो रहा है। इसमें छठ मैया की पूजा के साथ भगवान भास्कर की उपासना की जाती है। महिलाएं बच्चों के स्वास्थ्य, सफलता और दीर्घायु के लिए 36 घंटे तक कठिन उपवास करती हैं। यहां भी पूर्वांचल के लोग बड़े उत्साह से यह पर्व मनाते हैं। यह पर्व पांच से आठ नवंबर तक चलेगा। छठ पूजा में पानी में खड़े होकर स्नान, उपवास, और सूर्य को अर्घ्य देना शामिल है। प्रकृति का छठे अंश होने के कारण इस देवी का नाम षष्ठी देवी रखा गया। यह देवी बालकों की रक्षा और आयु प्रदान करती हैं। स्कंद पुराण में इन्हें ही देवी कात्यायनी कहा गया है। षष्ठी तिथि शिशुओं के संरक्षण व संवर्धन की देवी हैं।

ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास ने बताया कि छठ व्रती सात नवंबर को अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देंगी। इस दिन षष्ठी तिथि को छठी मैया का पूजन विधि-विधान के साथ होगा। सात नवंबर को धृति व रवियोग का संयोग बना रहेगा। व्रती जल में खड़े होकर पवित्रता के साथ फल, मिष्ठान, नारियल, पान-सुपारी, फूल, अरिपन से भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर परिवार की कुशलता के लिए प्रार्थना करेंगी। शुक्रवार आठ नवंबर को कार्तिक शुक्ल सप्तमी तिथि को सर्वार्थ सिद्धि योग व रवि योग में व्रती उदीयमान सूर्य उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ चार दिवसीय पर्व को संपन्न करेंगी।

ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास ने बताया कि प्रत्येक वर्ष लोक आस्था का महापर्व छठ मनाया जाता है। छठ के पर्व को आस्था का महापर्व माना गया है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि पर छठी मैया की पूजा की जाती है। मान्यता है कि छठ पूजा करने वाले भक्तों को सुख-समृद्धि, धन, वैभव, यश और मान-सम्मान की प्राप्ति होती है। कहते हैं जो महिलाएं यह व्रत रखती हैं उनकी संतानों को दीर्घायु और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। इसके साथ यह व्रत करने से निरोगी जीवन का आशीर्वाद भी मिलता है। छठ पर्व भारत के कुछ कठिन पर्वों में से एक है जो 4 दिनों तक चलता है। इस पर्व में 36 घंटे निर्जला व्रत रख सूर्य देव और छठी मैया की पूजा की जाती है और उन्हें अर्घ्य दिया जाता है। यह व्रत मनोकामना पूर्ति के लिए भी किया जाता है। महिलाओं के साथ पुरुष भी यह व्रत करते हैं। कार्तिक माह की चतुर्थी तिथि पर नहाय-खाय होता है, इसके बाद दूसरे दिन खरना और तीसरे दिन डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद व्रत का पारण किया जाता है।

नहाय खाय से हो जाती है, छठ पूजा की शुरुआत

ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास ने बताया कि कार्तिक शुक्ल पक्ष कि चतुर्थी तिथि को छठ महापर्व कि पहली परंपरा का निर्वाह किया जाता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को नहाए-खाए के रूप में मनाया जाता है। इस परंपरा के अनुसार सबसे पहले घर की सफाई कर उसे शुद्ध किया जाता है। इसके पश्चात छठव्रती स्नान कर शुद्ध शाकाहारी भोजन ग्रहण कर व्रत की शुरुआत करते हैं। घर के अन्य सभी सदस्य व्रती सदस्यों के भोजन करने के बाद ही भोजन ग्रहण करते हैं। नियम के अनुसार, इस दिन भात, लौकी की सब्जी और दाल ग्रहण किया जाता है और खाने में सिर्फ सेंधा नमक का इस्तेमाल किया जाता है। इस दिन व्रत करने वाली महिलाएं और पुरुष एक समय का भोजन करके अपने मन को शुद्ध करते हैं। इस दिन से घर में शुद्धता का बहुत ध्यान रखा जाता है, और लहसुन-प्याज़ बनाने की मनाही हो जाती है।

6 नवंबर

खरना- दूसरे दिन रखते हैं, पूरे दिन का उपवास

ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास ने बताया कि छठ पूजा में दूसरे दिन को "खरना" के नाम से जाना जाता है। इस दिन व्रती पूरे दिन का उपवास रखती हैं। खरना का मतलब होता है, शुद्धिकरण। खरना के दिन शाम होने पर गुड़ की खीर का प्रसाद बना कर व्रती महिलाएं पूजा करने के बाद अपने दिन भर का उपवास खोलती हैं। फिर इस प्रसाद को सभी में बाँट दिया जाता है। इस प्रसाद को ग्रहण करने के बाद व्रतियों का 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू हो जाता है। इस दिन प्रसाद बनाने के लिए नए मिट्टी के चूल्हे और आम की लकड़ी का प्रयोग करना शुभ माना जाता है।

7 नवंबर

संध्या अर्घ्य में करते है, सूर्य की उपासना

भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्लेषक डा. अनीष व्यास ने बताया कि तीसरे दिन शाम के समय डूबते हुए सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है, जिसकी वजह से इसे "संध्या अर्घ्य" कहा जाता है। इस दिन व्रती महिलाएं भोर में सूर्य निकलने से पहले रात को रखा मिश्री-पानी पीती हैं। उसके बाद अगले दिन अंतिम अर्घ्य देने के बाद ही पानी पीना होता है। संध्या अर्घ्य के दिन विशेष प्रकार का पकवान "ठेकुवा" और मौसमी फल सूर्य देव को चढ़ाए जाते हैं, और उन्हें दूध और जल से अर्घ्य दिया जाता है।

8 नवंबर

उगते सूर्य के अर्घ्य के साथ संपन्न होती है छठ पूजा

कुण्डली विश्लेषक डा. अनीष व्यास ने बताया कि चौथे दिन उगते हुए सूर्य को अंतिम अर्घ्य दिया जाता है। व्रत रखने वाली महिलाएं और पुरुष छठी मईया और सूर्य देव से अपने संतान और पूरे परिवार की सुख-शांति और उन पर अपनी कृपा बनाये रखने की प्रार्थना करती हैं। इसके बाद व्रती घर के देवी-देवता की पूजा करते हैं, और फिर प्रसाद को खाकर व्रत का समापन करते हैं।

पौराणिक कथा

भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्लेषक डा. अनीष व्यास ने बताया कि छठ पर्व पर छठी माता की पूजा की जाती है, जिसका उल्लेख ब्रह्मवैवर्त पुराण में भी मिलता है। एक कथा के अनुसार

प्रथम मनु स्वायम्भुव के पुत्र राजा प्रियव्रत को कोई संतान नहीं थी। इस वजह से वे दुखी रहते थे। महर्षि कश्यप ने राजा से पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करने को कहा। महर्षि की आज्ञा अनुसार राजा ने यज्ञ कराया। इसके बाद महारानी मालिनी ने एक पुत्र को जन्म दिया लेकिन दुर्भाग्य से वह शिशु मृत पैदा हुआ। इस बात से राजा और अन्य परिजन बेहद दुखी थे। तभी आकाश से एक विमान उतरा जिसमें माता षष्ठी विराजमान थीं। जब राजा ने उनसे प्रार्थना की, तब उन्होंने अपना परिचय देते हुए कहा कि- मैं ब्रह्मा की मानस पुत्री षष्ठी देवी हूं। मैं विश्व के सभी बालकों की रक्षा करती हूं और निसंतानों को संतान प्राप्ति का वरदान देती हूं।" इसके बाद देवी ने मृत शिशु को आशीष देते हुए हाथ लगाया, जिससे वह जीवित हो गया। देवी की इस कृपा से राजा बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने षष्ठी देवी की आराधना की। ऐसी मान्यता है कि इसके बाद ही धीरे-धीरे हर ओर इस पूजा का प्रसार हो गया।

धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व

भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्लेषक डा. अनीष व्यास ने बताया कि छठ पूजा धार्मिक और सांस्कृतिक आस्था का लोकपर्व है। यही एक मात्र ऐसा त्यौहार है जिसमें सूर्य देव का पूजन कर उन्हें अर्घ्य दिया जाता है। हिन्दू धर्म में सूर्य की उपासना का विशेष महत्व है। वे ही एक ऐसे देवता हैं जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से देखा जाता है। वेदों में सूर्य देव को जगत की आत्मा कहा जाता है। सूर्य के प्रकाश में कई रोगों को नष्ट करने की क्षमता पाई जाती है। सूर्य के शुभ प्रभाव से व्यक्ति को आरोग्य, तेज और आत्मविश्वास की प्राप्ति होती है। वैदिक ज्योतिष में सूर्य को आत्मा, पिता, पूर्वज, मान-सम्मान और उच्च सरकारी सेवा का कारक कहा गया है। छठ पूजा पर सूर्य देव और छठी माता के पूजन से व्यक्ति को संतान, सुख और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है।

सांस्कृतिक रूप से छठ पर्व की सबसे बड़ी विशेषता है इस पर्व की सादगी, पवित्रता और प्रकृति के प्रति प्रेम।

खगोलीय और ज्योतिषीय महत्व

वैज्ञानिक और ज्योतिषीय दृष्टि से भी छठ पर्व का बड़ा महत्व है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि एक विशेष खगोलीय अवसर, जिस समय सूर्य धरती के दक्षिणी गोलार्ध में स्थित रहता है। इस दौरान सूर्य की पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर सामान्य से अधिक मात्रा में एकत्रित हो जाती है। इन हानिकारक किरणों का सीधा असर लोगों की आंख, पेट व त्वचा पर पड़ता है। छठ पर्व पर सूर्य देव की उपासना व अर्घ्य देने से पराबैंगनी किरणें मनुष्य को हानि न पहुंचाएं, इस वजह से सूर्य पूजा का महत्व बढ़ जाता है।

कौन हैं छठी मैया, छठ पर्व पर सूर्य देव के साथ क्यों किया जाता है इनका पूजन?

छठी मैया को ऐसी देवी माना जाता है, जो अपने भक्तों को स्वास्थ्य, समृद्धि और खुशी प्रदान करती हैं। वह प्रकृति की पोषण और सुरक्षात्मक शक्तियों का प्रतिनिधित्व करती हैं और उनकी पूजा करने से कल्याण और सद्भाव का आशीर्वाद मिलता है।

छठ महापर्व आज नहाय खाय के साथ शुरू हो गया है। इस दौरान भक्त सूर्य देव और छठ माता की पूजा करते हैं। छठ माता को आम बोलचाल की भाषा में छठी मैया भी कहा जाता है। छठी मैया एक पूजनीय हिंदू देवी हैं। मान्यताओं के अनुसार, छठी मैया सूर्य देव की बहन और देवों के देव महादेव के पुत्र कार्तिकेय की पत्नी है।

छठी मैया को ऐसी देवी माना जाता है, जो अपने भक्तों को स्वास्थ्य, समृद्धि और खुशी प्रदान करती हैं। वह प्रकृति की पोषण और सुरक्षात्मक शक्तियों का प्रतिनिधित्व करती हैं और उनकी पूजा करने से कल्याण और सद्भाव का आशीर्वाद मिलता है। इतना ही नहीं माना जाता है कि छठी मैया की पूजा करने से संतान प्राप्ति होती है एवं उनकी रक्षा का आशीर्वाद भी मिलता है।

छठ पर्व से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं और धार्मिक मान्यताएं प्रचलित हैं, जो इस पर्व के महत्व और इसकी दिव्यता को दर्शाती हैं।

महाभारत की कथा

महाभारत काल से जुड़ी एक कथा के अनुसार, जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए थे, तो द्रौपदी ने छठ व्रत का रखा था। उन्होंने सूर्य देव और छठी मैया की पूजा की, जिससे उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हुईं और पांडवों को उनका खोया हुआ राजपाट वापस मिल गया। यह कथा दर्शाती है कि छठ पूजा से भक्तों को कठिन परिस्थितियों से मुक्ति मिलती है।

भगवान राम और माता सीता की कथा

एक अन्य पौराणिक कथा भगवान राम और माता सीता से जुड़ी है। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान राम और सीता अयोध्या लौटे थे और उन्होंने अपना राज्याभिषेक किया था, तब उन्होंने कार्तिक मास में सूर्य देव की आराधना की थी। माता सीता ने छठ व्रत कर सूर्य देव और छठी मैया का आशीर्वाद प्राप्त किया था। इस प्रकार, यह परंपरा तब से चली आ रही है।

सूर्य पुत्र कर्ण की कथा

छठ पर्व सूर्य देव की पूजा का पर्व है, और इसकी एक कथा महाभारत के सूर्यपुत्र कर्ण से जुड़ी है। कर्ण सूर्य देव के परम भक्त थे और प्रतिदिन घंटों तक सूर्य की उपासना करते थे। सूर्य देव की कृपा से ही उन्हें उनकी महान शक्तियां प्राप्त हुई थीं। यह भी माना जाता है कि कर्ण ने छठ पर्व की परंपरा को आरंभ किया था।

छठी मैया की कथा

छठी मैया को प्रकृति की देवी और संतान की रक्षा करने वाली देवी माना जाता है। एक लोककथा के अनुसार, जब राजा प्रियव्रत और उनकी पत्नी मालिनी को संतान नहीं हो रही थी, तो उन्होंने महर्षि कश्यप के कहने पर यज्ञ किया। इस यज्ञ से उन्हें संतान प्राप्त हुई, लेकिन वह मृत पैदा हुई। तब राजा प्रियव्रत ने अपनी पत्नी के साथ कठोर तपस्या की और छठी मैया की आराधना की। दोनों की कठोर तपस्या से देवी प्रकट हुईं और उन्हें संतान का आशीर्वाद मिला।

छठ पूजा के दिन महिलाएं पैरों में पहनें ये आकर्षक बिछिया

छठ पूजा का त्योहार आज से शुरु हो चुका है। इस पर्व को दौरान नए वस्त्र और गहने पहनना शुभ होता है। अगर आप इस दिन पैरों की खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए आप छठ पूजा के दौरान ट्रेंडी बिछिया पहन सकते हैं।

छठ पूजा का इंतजार लोगों को काफी समय से होता है। आज से नहाय-खाय छठ पर्व की शुरुआत हो चुकी है। यह पर्व 4 दिन तक चलता है और 36 घंटे तक निर्जला व्रत रखा जाता है। छठ पर्व के दौरान खुद को स्टाइलिश बनाने के लिए आप तैयारी जरुर कर रहे होंगे। छठ पूजा के मौके पर पैरों की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए आप सुंदर बिछिया पहन सकते हैं। आइए जानते हैं छठ पूजा के लिए पैरों के आकर के हिसाब से बिछिया की नई और खूबसूरत डिजाइंस। इसके साथ ही बताएंगे इन्हें स्टाइलिश लुक देने के टिप्स-

पायल के साथ पहनें बिछिया

आपको बाजार में मन चाही फैंसी डिजाइन में और रंग-बिरंगी बिछिया देखने को मिल जाएगी। आजकल मार्केट में आपको पायल के साथ में जुड़ी हुई डिजाइन वाली खूबसूरत बिछिया देखने को मिल जाएंगी। रॉयल लुक पाने के लिए आप इसे गोल्डन कलर का भी पहन सकते हैं। इतना ही नहीं, पायल के साथ में आप हाथफूल की तरह दिखने वाली ब्रेसलेट स्टाइल जैसे पायल और बिछिया के साथ पहन सकते हैं।

स्टोन डिजाइन की बिछिया

अगर आप स्टोन वर्क काफी पसंद है तो यह आजकल काफी ट्रेंड में है। आप चाहें तो इसमें रेड और ग्रीन कलर के स्टोन वाली बिछिया को पहन सकती हैं। इस तरह की बिछिया देखने में काफी स्टाइलिश लुक देती हैं। आप चाहें तो एक ही पैर की अलग-अलग उंगलियों में अलग साइज और मिलते-जुलते शेप की बिछिया को पहन सकते हैं।

सिंपल डिजाइन की बिछिया

बाजार में कई तरह की सिंपल डिजाइन में आपको बिछिया मिल जाएगी। आप चाहे तो सिल्वर यानी चांदी की बिछिया मिल जाएंगे। चाहें तो इसमें आप अपनी पसंद से घुंघरू या स्टोन भी लगवा सकती हैं। इतना ही नहीं, अपनी पसंद के साइज भी एडजस्ट करवा सकते हैं।

नींद न आने की समस्या से रहते हैं परेशान तो सीपीएपी थेरेपी है फायदेमंद, जानिए फायदे और नुकसान

सीपीएपी थेरेपी के दौरान एक ऐसी मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, जो नींद के दौरान वायुमार्ग को खुला रखने के लिए हवा की एक स्थिर धारा प्रदान करती है। इस थेरेपी की सहायता से श्वांस संबंधी समस्या दूर होती है।

नई दिल्ली। सीपीएपी थेरेपी, जिसको स्लीप एपनिया और अन्य श्वास संबंधी समस्याओं के इलाज में बेहद फायदेमंद माना जाता है। इस थेरेपी की मदद से नींद से जुड़ी समस्याएं दूर होने के साथ नींद को बेहतर बनाने में बहुत कारगर होती है। लेकिन यह थेरेपी डॉक्टर के कहने पर ही ली जाती है। इस थेरेपी की मदद से बेहतर नींद आती है और व्यक्ति को खर्राटों की समस्या से भी राहत मिलती है।

सीपीएपी थेरेपी के दौरान एक ऐसी मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, जो नींद के दौरान वायुमार्ग को खुला रखने के लिए हवा की एक स्थिर धारा प्रदान करती है। इस थेरेपी की सहायता से वायुमार्ग को खुला रखा जाता है और इससे श्वांस संबंधी समस्या दूर होती है और अच्छी नींद मिलने में मदद मिलती है। इस थेरेपी के दौरान मुंह और नाक पर मास्क लगाया जाता है। ऐसे में आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि सीपीएपी थेरेपी के फायदे और यह कैसे कार्य करती है।

जानिए फायदे

इस थेरेपी को लेने के बहुत फायदे होते हैं। स्लीप एपनिया और अन्य नींद से संबंधित समस्याओं में सीपीएपी थेरेपी लेने से फायदा मिलता है। इसकी वजह से रोगियों के जीवन में और नींद की गुणवत्ता में सुधार होता है।

सीपीएपी थेरेपी के उपयोग से नींद की गुणवत्ता में सुधार होता है। अगर आपको रात में सही से नींद नहीं आती है, तो आप डॉक्टर की सलाह पर इस थेरेपी को ले सकते हैं।

सीपीएपी थेरेपी स्लीप एपनिया के रोगियों के लिए भी काफी असरदार साबित होती है।

इस थेरेपी को लेने से दिन की नींद और थकान से जुड़ी समस्या दूर होती है। अगर नींद की कमी होने से आपको थकान बनी रहती है, तो आपको यह थेरेपी लेने से लाभ मिलेगा।

इस थेरेपी की मदद से स्लीप एपनिया का इलाज होता है। जिससे हार्ट अटैक, हाई ब्लड प्रेशर और स्ट्रोक का जोखिम भी कम होता है।

सीपीएपी थेरेपी की मदद से डायबिटीज रोगियों को भी लाभ मिल सकता है।

इस थेरेपी से सीओपीडी के रोगियों में सांस लेने में सुधार कर सकती है।

कैसे काम करती है ये थेरेपी

इस थेरेपी के लिए एक मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। इस मशीन में मुख्य 3 घटक होते हैं। इसमें मोटर, मास्क और नली शामिल होती है।

इस थेरेपी के दौरान मशीन में मोटर दबाव पर हवा का लगातार प्रवाह उत्पन्न करती है।

इस दौरान रोगी को नाक और मुंह पर मास्क पहनाया जाता है और वायुमार्ग को खुला रखने के लिए मास्क हवा देता है।

नली के माध्यम से ही हवा पहुंचाई जाती है।

रोगी की स्थिति के अनुसार सीपीएपी थेरेपी मशीरन की सेटिंग की जाती है। हवा का प्रवाह कितना चाहिए यह स्लीप एपनिया की गंभीरता या अन्य कारकों पर निर्धारित होता है।

नुकसान

सीपीएजी थेरेपी कई रोगों से छुटकारा दिलाती है। लेकिन इसके भी अपने कुछ नुकसान होते हैं।

इस थेरेपी को लेने की वजह से लगातार वायुप्रवाह होता है और इसमें नाक बंद होने की समस्या हो सकती है।

सीपीएजी थेरेपी की वजह से नाक में जलन हो सकती है या फिर नाक बहने की समस्या होने लगती है।

इस थेरेपी के कारण ड्राई माउथ की समस्या हो सकती है।

सीपीएजी थेरेपी के दौरान यदि मास्क ठीक न पहना हो, तो सांस लेने में समस्या हो सकती है।

सीपीएजी थेरेपी में हवा निगलने के कारण गैस की समस्या हो सकती है।

'आप' सरकार की मुफ्त बस यात्रा योजना ने बनाया नया रिकॉर्ड

अब तक 150 करोड़ बार महिलाओं ने किया मुफ्त सफर

दिल्ली सरकार की पिंक टिकट योजना के सफलतापूर्वक पांच साल पूरे होने पर आप नेता रीना गुप्ता ने ट्वीट कर बताया कि दिल्ली सरकार की यह योजना लाखों महिलाओं के जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आई है। 2024 तक 150 करोड़ से ज्यादा पिंक टिकट जारी किए गए, जिससे न केवल महिलाओं को मुफ्त बस सेवा का लाभ मिला, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनने का एक मौका भी मिला। इस योजना की वजह से महिलाओं के लिए सार्वजनिक परिवहन पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित और सुलभ हुआ है। पिछले पांच सालों में बसों में महिलाओं की संख्या में 25 फीसद की बढ़ोतरी हुई है, जिसमें 15 फीसद महिलाएं पहली बार बिना किसी झिझक के बसों में सफर कर रही हैं।

सुषमा रानी

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा योजना में एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड स्थापित किया है। तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में, 2019 में भाई दूज के अवसर पर महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की गई थी। अब तक 150 करोड़ से अधिक बार महिलाओं ने दिल्ली की डीटीसी और क्लस्टर बसों में मुफ्त यात्रा की है। इस योजना की वजह से महिलाओं के बीच सार्वजनिक परिवहन का उपयोग बढ़ा है, जिसमें 15 फीसद नई महिला यात्रियों के जुड़ने के साथ ही 25 फीसद महिलाएं नियमित रूप से बसों में सफर करती हैं। इस खास अवसर पर अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट किया, ₹हर महीने लाखों महिलाएं पिंक टिकट का लाभ उठाकर मुफ्त सफर कर रही हैं, और उनकी बचत अब उनके परिवार की जरूरतों का सहारा बन रही है। एक बेटे और बड़े भाई के रूप में मेरा सपना है कि हर बेटी और बहन आत्मनिर्भर बने और अपने सपनों को पूरा कर सके।"

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस मौके पर एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि ये जानकर अच्छा लगा कि दिल्ली की बसों में अब तक 150 करोड़ से ज़्यादा पिंक टिकट बांटे जा चुके हैं और हर महीने लाखों महिलाओं को इस पिंक टिकट से फ्री सफ़र की सहूलियत मिल रही है। उनकी बचत अब उनके परिवार की ज़रूरतों में सहारा बन रही है। दिल्ली के बेटे और बड़े भाई के तौर पर मेरा सपना है कि हर बेटी और बहन आत्मनिर्भर बने और अपने सपनों को पूरा कर सके।

दिल्ली सरकार की पिंक टिकट योजना के सफलतापूर्वक पांच साल पूरे होने पर आप नेता रीना गुप्ता ने ट्वीट कर बताया कि दिल्ली सरकार की यह योजना लाखों महिलाओं के जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आई है। 2024 तक 150 करोड़ से ज्यादा पिंक टिकट जारी किए गए, जिससे न केवल महिलाओं को मुफ्त बस सेवा का लाभ मिला, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनने का एक मौका भी मिला। इस योजना की वजह से महिलाओं के लिए सार्वजनिक परिवहन पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित और सुलभ हुआ है। पिछले पांच सालों में बसों में महिलाओं की संख्या में 25 फीसद की बढ़ोतरी हुई है, जिसमें 15 फीसद महिलाएं पहली बार बिना किसी झिझक के बसों में सफर कर रही हैं।

सबसे खास बात यह है कि इस योजना ने सिर्फ यात्रा को आसान नहीं बनाया, बल्कि महिलाओं की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत किया है। पिंक टिकट के जरिए मिली बचत को ज्यादातर महिलाओं ने घरेलू खर्चों में या जरूरत के समय खर्च के लिए बचाया। 54 फीसद महिलाएं अपनी बचत का इस्तेमाल घर के खर्चों में करती हैं, जबकि 50 फीदस महिलाएं इसे एमरजेंसी फंड के रूप में सुरक्षित रख रही हैं।

दिल्ली सरकार की पिंक टिकट योजना ने पिछले पांच सालों में लाखों महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का हौसला दिया है, और ये केवल एक योजना नहीं, बल्कि महिलाओं की आजादी और उनके अधिकारों का प्रतीक बन गई है। इसका मकसद खास तौर पर गरीब और मध्यम वर्ग की महिलाओं को फ़ायदा पहुंचाना है। इस योजना को लागू करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि सरकार कितनी भी आर्थिक तंगी से जूझ रही हो, लेकिन यह योजना बंद नहीं होगी।

गौरतलब है कि दिल्ली सरकार ने भाई दूज, 2019 से ही डीटीसी बसों में महिलाओं के लिए मुफ़्त यात्रा की सुविधा शुरू की थी. इस योजना के तहत, महिलाओं को सिंगल जर्नी पास दिया जाता है. बसों में महिला यात्रा करने वाली महिलाओं को पिंक रंग का टोकन दिया जाता है, जिसे लेना ज़रूरी है। इस योजना के तहत डीटीसी और क्लस्टर बसों में सफर करने वाली महिलाओं को 10 रुपये के पिंक टिकट दिए जाते हैं, जिसके खर्च का वहन सरकार करती है। इसके बाद, दिल्ली सरकार इन पिंक टिकटों की कुल संख्या के आधार पर बस कंपनियों को भुगतान करती है। यह योजना पूरी तरह स्वैच्छिक है, महिलाएं चाहें तो इसका लाभ उठा सकती हैं, या वे अपनी मर्जी से सामान्य टिकट भी ले सकती हैं। दिल्ली सरकार की इस पहल की वजह से बसों में सफर करने वाली महिलाओं की संख्या में भी इजाफा हुआ है।

परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने नए मार्ग 783EXT पर बसों को हरी झंडी दिखा कर रवाना किया

सुषमा रानी

नयी दिल्ली। दिल्ली के बाहरी क्षेत्रों और ग्रामीण इलाक़ों को सार्वजनिक परिवहन से जोड़ने और परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में आज दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने नए बस मार्ग 783EXT पर बसों को हरी झंडी दिखा कर रवाना किया। ध्वजारोहण कार्यक्रम में पालम विधायक भावना गौड़ और बिजवासन विधायक भूपिंदर सिंह जून भी उपस्थित थे। इस नए बस रूट 783EXT पर बसें केंद्रीय सचिवालय से पालम में दादा देव मंदिर तक जायेंगी। 783EXT बस रूट की कुल लंबाई 23.5 किलोमीटर है। यह बस रास्ते में सभी प्रमुख स्थानों और शैक्षणिक संस्थानों को कवर करेगी। दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) द्वारा संचालित चार लो-फ्लोर इलेक्ट्रिक बसें इस मार्ग पर चलेंगी, जो यात्रियों के लिए पर्यावरण-अनुकूल यात्रा विकल्प प्रदान करेंगी।

नई बस सेवा को हरी झंडी दिखाते हुए, दिल्ली के परिवहन मंत्री श्री कैलाश गहलोत ने कहा, "इस नए बस मार्ग की शुरुआत सभी दिल्लीवासियों, विशेषकर बाहरी क्षेत्रों और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को बेहतर और विश्वसनीय सार्वजनिक परिवहन सेवा प्रदान करने की हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। मार्ग 783EXT के लॉन्च से स्थानीय निवासियों के लिए स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और कार्यस्थलों जैसे महत्वपूर्ण स्थानों तक पहुंचना आसान हो जाएगा। हमारा लक्ष्य दिल्ली के हर कोने को सार्वजनिक परिवहन से जोड़ना है ताकि लोग आसानी से यात्रा कर सकें।"

783EXT मार्ग से राज नगर, राज नगर एक्सटेंशन, द्वारका सहित बिजवासन और पालम के विभिन्न क्षेत्रों और शिक्षा भारती कॉलेज, विश्व भारती पब्लिक स्कूल, राष्ट्रीय मलेरिया अनुसंधान

संस्थान और केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय आने-जाने वाले लोगों को लाभ होने की उम्मीद है

783Ext (UP) का विस्तृत मार्ग

केंद्रीय सचिवालय ,गुरुद्वारा रकाब गंज ,केन्द्रीय टर्मिनल ,एन.डी.पी.ओ, गुरुद्वारा बंगला साहिब ,पटेल चौक ,आकाशवाणी भवन ,कृषि भवन ,उद्योग भवन ,जी ब्लॉक ,सेना भवन ,त्याग राजा मार्ग ,साउथ ब्लॉक ,तीन मूर्ति ,चाणक्य पुरी पुलिस स्टेशन ,रेलवे कॉलोनी ,बापूधाम ,ताज होटल,धौला कुआं,गोल्फ क्लब,राज रिफ लाइन,किर्बी स्थान ,सप्लाई डिपो,

जनक सेतु,नांगल राया,लाजवंती गार्डन,सागरपुर वशिष्ट पार्क,डेसू कॉलोनी, जनकपुरी,जनक सिनेमा,डाबरी चौराहा,डबरी गांव,दशरथपुरी,विजय एन्क्लेव,महावीर एन्क्लेव भाग II, III,एसएफएस फ्लैट सेक्टर-2,द्वारका सेक्टर 1/2,द्वारका सेक्टर-6 टेलीफोन एक्सचेंज,द्वारका सेक्टर 6/7 चौराहा,प्रिंस पार्क अपार्टमेंट,द्वारका सेक्टर-7 प्रिंस पार्क,द्वारका सेक्टर,द्वारका सेक्टर-6/7, 9/10 चौराहा,शिक्षा भारती पब्लिक स्कूल,अमराही क्रॉसिंग (रामफल चॉल),रॉयल रेजीडेंसी,राष्ट्रीय मलेरिया, अनुसंधान केंद्र,देव देव मंदिर (पालम)

783EXT(डाउन) का विस्तृत मार्ग

देव देव मंदिर (पालम),राष्ट्रीय मलेरिया, अनुसंधान केंद्र,रॉयल रेजीडेंसी,अमराही क्रॉसिंग (रामफल चॉल)शिक्षा भारती पब्लिक स्कूल,द्वारका सेक्टर-6/7, 9/10 चौराहा,द्वारका सेक्टर-7 प्रिंस पार्क,द्वारका सेक्टर,प्रिंस पार्क अपार्टमेंट,द्वारका सेक्टर 6/7 चौराहा,द्वारका सेक्टर-6 टेलीफोन एक्सचेंज,द्वारका सेक्टर 1/2,एसएफएस फ्लैट सेक्टर-2,महावीर एन्क्लेव भाग II, III,विजय एन्क्लेव,दशरथपुरी,डबरी गांव,डाबरी चौराहा,जनक सिनेमा,डेसू कॉलोनी, जनकपुरी,सागर पुर वशिष्ट पार्क,लाजवंती गार्डन,नांगल राया,जनक सेतु,आपूर्ति डिपो,किर्बी स्थान,राज रिफ लाइन,गोल्फ क्लब,धौला कुआं,ताज होटल,बापूधाम,रेलवे कॉलोनी,चाणक्य पुरी पुलिस स्टेशन,तीन मूर्ति,साउथ ब्लॉक,त्याग राजा मार्ग,सेना भवन,जी ब्लॉक,उद्योग भवन,कृषि भवन,आकाशवाणी भवन,पटेल चौक,गुरुद्वारा बंगला साहिब, एन.डी.पी.ओ, केन्द्रीय टर्मिनल, गुरुद्वारा रकाब गंज,केंद्रीय सचिवालय,इस बस मार्ग के शुरू होने से रोज़ाना सफ़र करने वाले हजारों निवासियों को आसानी होगी।

"सरकार स्वच्छ जल उपलब्ध कराने में पूरी तरह विफल रही है"

सुषमा रानी

नई दिल्ली। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेन्द्र यादव ने कहा कि यह बहुत बड़ी विडंबना है कि राजधानी दिल्ली में लाखों पूर्वांचल वासी आस्था, श्रद्धा, विश्वास की भावना के साथ छठ पर्व पर प्रदूषित यमुना के जहरीले पानी में डुबकी लगाकर और प्रातः सूर्य देवता को अर्घ देकर छठ मैया का पूजन करके अपने व्रत को संपूर्ण करने को मजबूर है। छठ पर्व जल में रहकर मनाने की परम्परा के कारण 3-4 दिन तक चलने वाला पर्व में पूर्वांचल श्रद्धालु प्रदूषित यमुना में छठ मैया के व्रत को पूरा करने की रस्म अदा करेंगे। उन्होंने कहा कि यमुना का जल जहरीला हो रहा है, इसके लिए जवाबदेही तय होनी चाहिए और मुख्यमंत्री आतिशी प्रदूषित यमुना में बढ़ते अमोनिया के स्तर की जिम्मेदारी लेते हुए पर्यावरण मंत्री से इस्तीफा लें।

यादव ने कहा कि पूर्वांचल वासी छठ श्रद्धालु हर वर्ष इस उम्मीद के साथ यमुना में डुबकी लगाकर अर्घ देने की उम्मीद करते है कि सरकार स्वच्छ जल की व्यवस्था कर देगी परंतु हर श्रद्धालुओं को मजबूरीवश प्रदूषित यमुना में छठ का व्रत संपूर्ण करना पड़ता, जो आम आदमी पार्टी की सरकार की सबसे बड़ी विफलता है, जबकि पूर्वांचलवासियों को केजरीवाल अपना वोट बैंक बताते है। उन्हांने कहा कि यमुना में प्रदूषण इतने खतरनाक स्तर पर है कि यमुना में पूजा करने वाले छठ श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य पर विपरित प्रभाव पड़ रहा है। यमुना के प्रदूषित जल में पूजा करने को मजबूर लाखों छठ श्रद्धालुओं की भावनाएं आहत

हुई है, जिसके लिए पूरी तरह आम आदमी पार्टी जिम्मेदार है।

यादव ने कहा कि केन्द्र की भाजपा और दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार हर वर्ष यमुना सफाई पर करोड़ों रुपये खर्च करके स्वच्छ बनाने का दावा तो करती हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा और आम आदमी पार्टी की दोनो सरकारों का यमुना की सफाई का काम सिर्फ दस्तावेजों तक सीमित रहता है। यमुना सफाई में करोड़ों रुपये का भ्रष्टाचार करके पिछले 11 वर्षों में अरविन्द केजरीवाल ने दिल्लीवालां को धोखा दिया है, जबकि उन्होंने कहा कि 2025 तक यमुना को पूरी तरह साफ कर देंगे।

उन्होंने कहा कि यमुना किनारे छठ घाटां पर छठ श्रद्धालुओं के पर्याप्त व्यवस्थाएं उपलब्ध कराने में भी विफल साबित रही है। दिल्ली कांग्रेस के बार-बार चेताने के बावजूद सरकार ने घाटों की सफाई पर कोई खास ध्यान नही दिया। घाटों पर सरकारी व्यवस्थाऐं पर्याप्त नही है जबकि साल-दर-साल, केजरीवाल और उनकी पार्टी लगभग 1000 छठ घाट के निर्माण सहित यमुना में स्वच्छ पानी देने का वादा किया परंतु यमुना मैली की मैली ही रही।

उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी और भाजपा की आरोप प्रत्यारोप की राजनीति का भुगतान दिल्ली की जनता भुगत रही है। क्यों हरियाणा द्वारा छठ पर्व से पहले यमुना में साफ पानी नही छोड़ा, जबकि कांग्रेस की दिल्ली सरकार 3 दिन पहले हरियाणा सरकार से अनुरोध करके छठ श्रद्धालुओं के लिए साफ पानी उपलब्ध कराती थी, फिर आम आदमी पार्टी दिल्लीवालों की श्रद्धा और आस्था के प्रति संवेदनशील क्यों नही है?

दिल्ली में यूथ कांग्रेस के चुनाव में हुई है बड़ी धांधली : गुरचरन सिंह राजू

सुषमा रानी

नई दिल्ली। यूथ कांग्रेस के चुनाव नतीजे आ चुके हैं परन्तु इस यूथ कांग्रेस चुनाव में बड़ी धांधली हुई है। प्रैस क्लब ऑफ इंडिया में पत्रकारों को सम्बोधित करते हुए अपनी नाराज़गी व्यक्त करते हुए ज़िला कृष्णा नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गुरचरण सिंह राजू ने दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव पर दिल्ली यूथ कांग्रेस के चुनाव में बड़ी धांधली का आरोप लगाते हुए कहा कि यह कांग्रेस पार्टी की छवि को लगातार दिल्ली में धूमिल कर रहे हैं। श्री गुरचरण सिंह ने अपने संबोधन में नाराज़गी जताते हुए कहा कि दिल्ली यूथ कांग्रेस का चुनाव बहुत निष्पक्ष होता है बल्की हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी के आदेश की भी देवेंद्र यादव जी ने धज्जियां उड़ाई हैं। हालांकि माननीय राहुल गांधी ने कहा था कि युवाओं को अपना चुनाव ख़ुद लड़ने दो। उन्होंने यहां तक कहा था कि यूथ कांग्रेस चुनाव में कोई बड़ा नेता हस्तक्षेप नहीं करेगा और न ही किसी विशेष एक प्रत्याशी के स्पोर्ट में वोट देने की अपील करेगा परन्तु दिल्ली यूथ प्रदेश कांग्रेस के चुनाव में देवेंद्र यादव जी ने उनकी बात को अनसुना कर के लोगों को एक पक्ष में वोट डालने की अपील की जिस बड़ी संख्या में युवाओं के दिल को ठेस पहुंची है और वह बहुत आहत हैं।

गुरचरण सिंह राजू ने कहा कि दिल्ली प्रदेश कार्यालय से फोन कर के पूर्व पार्षद, ब्लॉक अध्यक्ष, ऑब्जर्वर और कार्यकर्ताओं को प्रत्याशी अक्षय लाकड़ा के पक्ष में वोट डालने के लिए कहा गया था। बल्की दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष श्री देवेंद्र यादव जी ने लोगों को डरा धमका कर प्रत्याशी अक्षय लाकड़ा को वोट डलवाए।

जिला कृष्णा नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गुरचरण सिंह राजू ने दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पर यह भी आरोप लगाया कि उत्तराखंड पंजाब के चुनाव में साज़िश करके कांग्रेस को हराया गया है। उन्होंने कहा कि अब तक जितने भी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं सभी ने बड़ी ईमानदारी से अपना काम किया है लेकिन देवेंद्र यादव जी हैं जो बेईमानी पर उतरे हुए हैं।

जिला कृष्णा नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि जिला अध्यक्ष के पूछे बिना हमारे ज़िले के वार्ड बना रहे हैं। जगतपुरी वार्ड का अध्यक्ष राजीव कुमार ढिल्लो को बनाया गया है जबकि सब को मालूम है कि वह एक अपराधी है जिस पर अपराधिक मामले चल रहे हैं। इसके अलावा आनंद विहार में रोहित रस्तोगी को वार्ड अध्यक्ष नियुक्त किया है जिसे कोई नहीं जानता है।

पत्रकारों के एक प्रशन क्या आप ज़िला कृष्णा नगर अध्यक्ष पद या कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देंगे ? के जवाब पर श्री गुरचरण सिंह राजू ने उत्तर देते हुए कहा कि मैं जिला अध्यक्ष के रूप में काम नहीं कर सकता अगर मुझे पार्टी किसी और पद पर कार्य करने को कहती है तो मैं करूंगा। मैं कांग्रेस का सिपाही हूं और पार्टी में कार्यकर्ता के रुप में अपने नेता राहुल गांधी जी के साथ रहूंगा। उन्होंने कहा कि पार्टी में अपनी बात को स्पष्ट रूप से सभी को रखने का अधिकार है जो हमने उससे आप सब को अवगत कराया है। आखिरी में एक बार फिर उन्होंने दोहराया कि मैं दिल्ली युवा कांग्रेस चुनाव की गिनती दोबारा चाहता हूं ताकि जो धांधली हुई है उन युवाओं को इंसाफ मिले। उन्होंने यह भी कहा कि अगर ऐसा नहीं होता है तो फ़िर मजबूरी में मुझे इस्तीफ़ा के लिए सोचना होगा।

खाद्य-आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन ने एनएफएसए और ओएनओआरसी योजना के तहत दिल्ली में मुफ्त राशन के वितरण की समीक्षा की

नई दिल्ली (सुषमा रानी)

नई दिल्ली। 5 नवंबर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और जन नेता अरविंद केजरीवाल के मार्गदर्शन में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन ने दिल्ली में जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुँचाने और सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के विशेष आयुक्त (एफ एंड एस) और सहायक आयुक्तों (एसी) के साथ मिलकर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) और वन नेशन वन राशन कार्ड (ओएनओआरसी) योजना के तहत मुफ्त राशन के वितरण की समीक्षा की।

बैठक के दौरान खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन को जानकारी दी गई कि नवंबर 2024 के लिए एनएफएसए के तहत राशन लाभार्थियों को राशन वितरण 1 नवंबर से शुरू कर दिया गया है, और अब तक लगभग 50 फीसद राशन कोटा लाभार्थियों को वितरित किया जा चुका है। इसके साथ ही, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आने वाले

राशन लाभार्थियों के अलावा वन नेशन वन राशन कार्ड लाभार्थियों को भी नवंबर 2024 के लिए पात्रता के अनुसार मुफ्त राशन दिया जा रहा है।

खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन ने कहा कि राशन पोर्टेबिलिटी ओएनओआरसी के तहत दिल्ली में पर्याप्त राशन उपलब्ध है। छठ पूजा को ध्यान में रखते हुए, दिल्ली में रहने वाले प्रवासी लोग ओएनओआरसी के माध्यम से अन्य राज्यों के राशन कार्ड से सुविधाजनक तरीके से राशन प्राप्त कर सकते हैं। इमरान हुसैन ने बताया कि ओएनओआरसी योजना के तहत नवंबर 2024 में दिल्ली में राशन पोर्टेबिलिटी के माध्यम से एक लाख से अधिक प्रवासी राशन लाभार्थियों को राशन वितरित किया गया है।

बैठक के दौरान इमरान हुसैन ने राजधानी दिल्ली में बिना राशन कार्ड वाले प्रवासी मजदूरों के मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की समीक्षा की और प्रवासी मजदूरों को उनकी पात्रता के आधार पर राशन कार्ड जारी करने के निर्देश दिए। इमरान हुसैन ने खाद्य-आपूर्ति विभाग को प्राथमिकता के आधार पर इस मामले में तेजी लाने का निर्देश देते हुए कहा कि प्रवासी मजदूरों के हितों का ध्यान रखते हुए, उन्हें बिना किसी देरी के, उनकी पात्रता और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार राशन कार्ड जारी किया जाना चाहिए।

अपराध के हथियार के साथ दो हत्यारे गिरफ्तार

सुषमा रानी, दिल्ली। हत्या में शामिल दो व्यक्तियों को पूर्वी जिला, दिल्ली के कल्याणपुरी पुलिस थाने के कर्मियों द्वारा गिरफ्तार किया गया तथा अपराध का हथियार, खून से सने कपड़े बरामद किए गए। पूर्वी दिल्ली पुलिस उपायुक्त अर्पूवा गुप्ता के अनुसार 02 नवंबर को खिचड़ीपुर, दिल्ली में झगड़े के बारे में एक पीसीआर कॉल आई। एसआई भानुसिंह ने मौके पर पहुंचने पर देखा कि कॉलर, मनीष कुमार निवासी खिचड़ीपुर, दिल्ली, उम्र 24 वर्ष, घर की तीसरी मंजिल की रसोई में मौजूद था। पूछताछ में, कॉलर ने अपने साले अभिषेक उर्फ हल्लन की हत्या करने और शव को कमरे में बंद करने की बात कबूल की थी। बगल का कमरा बाहर से बंद था। कमरे का ताला तोड़ा गया और एक पुरुष का शव खून से लथपथ चटाई में लिपटा हुआ मिला। शरीर में कोई हरकत नहीं थी और गर्दन और माथे पर चाकू के कई वार के निशान थे। चारों तरफ खून बिखरा हुआ था। अपराध स्थल का निरीक्षण क्राइम टीम और एफएसएल विशेषज्ञ ने किया। शव को पीएम के लिए मोर्चरी में भेज दिया गया। पूछताछ में आरोपी मनीष ने बताया कि उसकी बहन कोमल ने करीब 2 साल पहले मृतक के साथ भागकर शादी कर ली थी। शादी के कुछ समय बाद ही दोनों के बीच संबंध खराब हो गए और मृतक अपनी बहन को किसी न किसी बहाने से अपमानित और परेशान करने लगा। वह अपनी अनुचित मांगों को पूरा करने के लिए अपनी बहन से पैसे मांगता था और मना करने पर अपनी बहन के साथ बुरी तरह मारपीट करता था। रोज-रोज की प्रताड़ना से तंग आकर वह घर छोड़कर अपने मायके चली गई। आज उसका जीजा मृतक को वापस लेने उसके घर आया था। जब उसने मना किया तो उसने चाकू निकाल लिया और सभी को जान से मारने की धमकी दी। वह नशे में लग रहा था। फोन करने वाले ने विरोध किया लेकिन आरोपी ने उसे भी धायल कर दिया। इससे क्रोधित होकर उसने मृतक का गला पकड़ लिया और उसके सिर पर कई बार चक्की पटक दी और उसके सिर और गले पर कई बार चाकू से वार किया, जब तक कि उसकी मौत नहीं हो गई। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसकी निशानदेही पर अपराध का खून से सना हथियार यानी चाकू और खून से सने कपड़े बरामद कर लिए गए हैं। बाद में आरोपी के साथी मुकेश कुमार निवासी खिचरीपुर, दिल्ली, उम्र 19 वर्ष को भी आरोपी की निशानदेही पर गिरफ्तार कर लिया गया। आगे की जांच जारी है।

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ग्रेनो प्राधिकरण को दिया करीब 47 करोड़ रुपये भुगतान का आदेश, 20 साल पुराना है मामला

परिवहन विशेष न्यूज

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले से जोरदार झटका दिया है। दरअसल 20 साल पहले ग्रेनो ने 240 कर्मचारियों माली और सफाईकर्मियों को नौकरी से हटा दिया था। जिसको लेकर अब कोर्ट को फैसला प्राधिकरण के खिलाफ आया है। कोर्ट ने अपने फैसले में फिर से नौकरी पर रखने के साथ ही 46 करोड़ 36 लाख 80 हजार रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया।

ग्रेटर नोएडा। करीब 20 वर्ष पहले ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण (Greater Noida Authority) से नौकरी से हटाए गए 240 कर्मचारियों माली व सफाईकर्मी के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्राधिकरण को बड़ा झटका दिया है। प्राधिकरण की याचिकाओं को खारिज करते हुए 46 करोड़ 36 लाख 80 हजार रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है।

जिलाधिकारी गौतमबुद्ध नगर को 90 दिन में आदेश का पालन सुनिश्चित कराने को कहा है। साथ बी कार्य पर बहाल करने का भी आदेश दिया है। ग्रेटर नोएडा माली व सफाई कामगार यूनियन के बैनर तले कर्मी कानून लडाई लड़ रहे थे।

प्राधिकरण ने साल 2003 में 240 कर्मचारियों को नौकरी से हटाया

यूनियन के महामंत्री रामकिशन सिंह व मंत्री टीकम सिंह ने बताया कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा किए जा रहे आर्थिक शोषण के खिलाफ व नियमितीकरण के लिए कर्मचारियों ने 1998 से सीटू के नेतृत्व में आवाज उठाना शुरू किया था। प्राधिकरण ने वर्ष 2003 में 240 कर्मचारियों को नौकरी से हटा दिया था।

इसके विरोध में कर्मचारी कोर्ट चले गए थे। 24 साल की लंबी लड़ाई के बाद 16 अक्टूबर को इलाहबाद हाई कोर्ट ने कर्मचारियों के हक में आदेश दिया है। श्रम न्यायालय द्वारा कर्मचारियों के पक्ष में किए गए अवार्ड के खिलाफ प्राधिकरण द्वारा दायर की गई सभी 20 याचिकाओं को खारिज करते हुए कर्मचारियों के पक्ष में निर्णय दिया है।

90 दिन के भीतर आदेश का हो पालन-कोर्ट

कोर्ट ने जिलाधिकारी आदेश दिया है कि 90 दिन के भीतर आदेश का पालन सुनिश्चित कराते हुए प्राधिकरण से धनराशि वसूलकर कर्मचारियों को भुगतान कराया जाए। साथ ही विवाद से संबंधित सभी श्रमिकों को क्षतिपूर्ति सहित सेवा के पुराने क्रम में कार्य पर बहाल कराया जाए।

दरअसल मामले में श्रम विभाग द्वारा चार जनवरी 2024 को 46 करोड़ 36 लाख 80 हजार रुपये की वसूली प्रमाण पत्र जारी कर जिलाधिकारी से प्राधिकरण से वसूल कर कर्मचारियों को भुगतान करने का अनुरोध किया था। अवार्ड का पालन करने से बचने के लिए प्राधिकरण ने हाई कोर्ट में 20 रिट याचिकाएं दाखिल की थीं।

'फिर से होगी निर्णायक लड़ाई'

कर्मियों ने कहा कि यदि जिला प्रशासन ने प्राधिकरण से हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं कराया गया तो फिर से निर्णायक लड़ाई लड़ी जाएगी। इस दौरान सीटू जिलाध्यक्ष गंगेश्वर दत्त शर्मा, किसान सभा के जिलाध्यक्ष डा. रूपेश वर्मा, यूनियन से ज्ञानचंद, धनपाल, अमरपाल, बादल, वीरेंद्र, साहब राम, धीरज बाली, वीर सिंह आदि मौजूद रहे।

चुनाव से डर गई भाजपा, बदलवा दी तारीख; अखिलेश यादव ने इन मुद्दों पर बीजेपी को घेरा

पूर्व सीएम अखिलेश यादव मंगलवार को गाजियाबाद पहुंचे। इस दौरान अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी ने हार के डर की वजह से चुनाव की तारीख ही बदलवा दी। अखिलेश ने कई बड़े मुद्दों पर भाजपा को घेरा है। वहीं अखिलेश ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी दिया।

गाजियाबाद। UP By-Election 2024 समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मंगलवार को बीजेपी पर जमकर निशाना साधा।

अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा ने हार के डर से चुनाव की तारीख बदलवा दी है, क्योंकि इसका असर महाराष्ट्र के चुनाव तक पड़ेगा।

इस दौरान अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं को हर बूथ को जीतने का मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि गाजियाबाद में जितने भी बड़े काम हुए हैं, वह समाजवादी सरकार ने कराए हैं।

पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने ई-रिक्शा संचालन बंद करने, कोर्ट में वकीलों पर लाठीचार्ज, फर्जी एनकाउंटर, सबका साथ, सबका विकास वाले नारे देने समेत के मुद्दों पर अपनी बात रखी। वह हापुर रोड स्थित इंपीरियल गार्डन में कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, इसी दौरान उन्होंने ये बातें कहीं।

परिसीमन के बाद नहीं जीती महिला प्रत्याशी

गाजियाबाद शहर विधानसभा सीट का परिसीमन होने के बाद एक बार भी महिला प्रत्याशी को जीत हासिल नहीं हुई है। इसकी एक खास वजह यह भी है कि प्रमुख दलों ने महिला नेता को टिकट देकर उम्मीदवार ही नहीं बनाया है। इस बार भी उपचुनाव में प्रमुख दलों ने महिला उम्मीदवार को प्रत्याशी नहीं बनाया है। 14 में से महज एक महिला प्रत्याशी चुनाव के मैदान में है।

गाजियाबाद शहर विधानसभा सीट पर प्रमुख दलों में से भाजपा ने सुनीता दयाल को परिसीमन से पहले वर्ष 2004 के उपचुनाव में प्रत्याशी बनाया था, इसमें वह तीसरे नंबर पर रही थीं। इसके बाद 2007 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने इस सीट पर सुनील शर्मा को प्रत्याशी बनाया, उन्होंने जीत हासिल की। वर्ष 2012 में परिसीमन के बाद साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र अलग बन गया और वहां पर सुनील शर्मा को टिकट देकर भाजपा ने प्रत्याशी बनाया।

गाजियाबाद शहर विधानसभा सीट पर अतुल गर्ग को प्रत्याशी बनाया, वह चुनाव में हारे लेकिन 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने दोबारा अतुल गर्ग पर ही भरोसा जताते हुए उनको टिकट देकर चुनाव के मैदान में उतारा और उन्होंने जीत हासिल की।

गाजियाबाद शहर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में 4.61 लाख से अधिक मतदाता मतदान करेंगे, इनमें महिला मतदाताओं की संख्या 2.07 लाख से अधिक है। इस सीट पर उपचुनाव में कुल 14 प्रत्याशी मैदान में हैं, इनमें एक महिला प्रत्याशी हिंदुस्थान निर्माण दल से पूनम हैं।

नाराज लोगों की नाराजगी करें दूर : भूपेंद्र चौधरी

यह उपचुनाव केवल चुनाव नहीं, सभी की प्रतिष्ठा से जुड़ा लक्ष्य है। सभी कार्यकर्ताओं को बूथ पर डटे रहना है। मतदान से पहले नाराज लोगों की नाराजगी हर हाल में दूर करनी है। यह बातें सोमवार को नेहरू नगर स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में गाजियाबाद शहर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के मद्देनजर आयोजित बूथ सम्मेलन में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कार्यकर्ताओं से कही।

उन्होंने कहा कि चुनाव में सभी बूथ प्रभारी व बूथ की टीम लोगों से लगातार संपर्क में रहे। छोटी-छोटी बैठकें कर अधिकाधिक लोगों से संपर्क करें। भाजपा के पश्चिमी क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष सतेंद्र सिसोदिया, भाजपा महानगर अध्यक्ष संजीव शर्मा, सांसद अतुल गर्ग, क्षेत्रीय प्रभारी सुभाष यदुवंश, प्रदेश मंत्री बसंत त्यागी सहित अन्य मौजूद थे।

गुरुग्राम की 11 परियोजानाओं को 250 करोड़, जानिए कौन से हैं प्रोजेक्ट जिनसे बदलेगी शहर की तस्वीर

गुरुग्राम। हाई पावर वर्कस परचेज कमेटी (एचपीडब्ल्यूपीसी, HPWPC) बैठक में गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (GMDA) की 249.77 करोड़ रुपये की 11 बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं के आवंटन को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी (Haryana CM Nayab Saini) की अध्यक्षता में यह बैठक मंगलवार को चंडीगढ़ में हुई।

बैठक में स्वीकृत परियोजनाएं सड़क के बुनियादी ढांचे को और बेहतर बनाने, कनेक्टिविटी बढ़ाने, सार्वजनिक परिवहन सेवाओं में सुधार, पैदल यात्रियों की सुरक्षा को सुविधाजनक बनाने और शहर में जल आपूर्ति का समान वितरण करने के लिए डिजाइन की गई हैं।

सड़कों की मरम्मत के लिए 166 करोड़

गुरूरुग्राम में 64 किलोमीटर मास्टर सेक्टर डिवाइडिंग सड़कों और 17.2 किलोमीटर सर्विस सड़कों की विशेष मरम्मत के लिए 166 करोड़ रुपये के कार्यों को आवंटन की मंजूरी दी गई।

बस डिपो और बस क्यू शेल्टर बनेंगे

भविष्य में नागरिकों की सार्वजनिक परिवहन सेवाओं की बढ़ती मांग को पूरा करने और गुरुग्राम के सभी हिस्सों में निर्बाध सार्वजनिक परिवहन सेवाएं प्रदान करने के लिए काम किया जाएगा। शहर को पर्याप्त बुनियादी ढांचे से लैस करने के लिए गुरुग्राम में अतिरिक्त बस डिपो और बस क्यू शेल्टर के विकास की सुविधा के लिए जीएमडीए की 50.77 करोड़ रुपये की तीन परियोजनाओं को आवंटन के लिए मंजूरी दी गई।

सेक्टर-48 में ई-बसों के लिए डिपो बनेगा

जीएमडीए के मोबिलिटी डिवीजन द्वारा किए जाने वाले कार्यों में गुरुग्राम के सेक्टर-48 में ई-बसों के लिए बस डिपो का विकास, गुरुग्राम के सेक्टर 68-95 में सदर्न पेरिफेरल रोड से नदर्न पेरिफेरल रोड तक जीएमडीए क्षेत्र में बस क्यू शेल्टरों का विकास किया जाएगा। साथ ही गुरुग्राम के सेक्टर 99-115 में द्वारका एक्सप्रेस-वे (Dwarka Expressway) के साथ जीएमडीए क्षेत्र में बस क्यू शेल्टरों का विकास शामिल है। इस परियोजना के अंतर्गत करीब 154 नए बस क्यू शेल्टर बनाए जाएंगे।

चार फुट ओवर ब्रिज बनेंगे

इसके अतिरिक्तए पैदल यात्रियों की सुरक्षित आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए फुट ओवर ब्रिज (Foot Over Bridge) के निर्माण कार्य को भी मंजूरी दी गईए जिसके तहत जीएमडीए 16 करोड़ रुपये की लागत से शहर में चार फुट ओवर ब्रिज बनाएगा। सेक्टर-14 मार्केट, सोहना रोड पर रहेजा माल के पास, सोहना रोड पर सीडी चौक पर और शीतला माता रोड पर फुट ओवर ब्रिज बनाए जाएंगे।

दिल्ली-एनसीआर वालों के लिए अच्छी खबर, कुंभ मेले पर यहां से सीधे प्रयागराज के लिए मिलेंगी बसें

अगले साल के शुरू में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ मेले की शुरुआत होने वाली है। इसको देखते हुए अब नोएडा प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। अब दादरी से श्रद्धालुओं को सीधे प्रयागराज जाने के लिए रोडवेज बस की सेवा मिले। इस क्षेत्र में काम तेजी से हो रहा है। जिसकी शुरुआत दिसंबर से शुरू होगी।

नोएडा। जनवरी में प्रयागराज में महाकुंभ मेले की शुरुआत होने जा रही है। इस अवसर पर दादरी क्षेत्र के श्रद्धालुओं को सीधे प्रयागराज जाने के लिए रोडवेज बस की सौगात मिलने जा रही है, जिसकी शुरुआत दिसंबर से होगी।

आर्य प्रतिनिधि सभा के जिला उपाध्यक्ष ने सिकंदराबाद डिपो एआरएम से मांग की कि सिकंदराबाद डिपो से प्रयागराज को संचालित होने वाली बस सेवा को दादरी होकर चलाया जाए। उन्होंने बताया कि प्रयागराज में आयोजित हो रहे महाकुंभ के मद्देनजर सिकंदराबाद से प्रयागराज को श्रद्धालुओं के हित में सीधी सेवा संचालित करा रहे हैं।

एआरएम सिकंदराबाद से मिली सहमति

जनहित में मांग है कि इस सेवा में दादरी को भी लिंक किया जाए जिससे कि दादरी तहसील के श्रद्धालुओं की एक बहुत बड़ी आबादी को भी प्रयागराज के लिए सीधी सेवा दादरी बस स्टैंड से उपलब्ध हो सके। उसके लिए एआरएम सिकंदराबाद ने अपनी सहमति दे दी है।

यह बस सेवा हमेशा के लिए रहेगी जारी

एआरएम सिकंदराबाद डिपो ने बताया कि दिसंबर में डिपो को 20 बसें मिल रही हैं। उनमें दो बसें नए साल पर दिल्ली से दादरी, सिकंदराबाद वाया कानपुर होते हुए प्रयागराज के लिए चलाई जाएंगी। यह बस सेवा हमेशा के लिए जारी रहेगी। दादरी के लोगों का सीधी कनेक्टिविटी प्रयागराज से होगी। समय सारणी बस सेवा शुरू हो जाने के बाद तय होगी।

खरीदारों को लोकेशन चुनने की मिली छूट

यमुना प्राधिकरण (Yamuna Authority) की फ्लैट योजना को खरीदार नहीं मिल रहा है। डेढ़ महीने बाद भी अधिकांश फ्लैट खाली पड़े हुए हैं। केवल एक ही श्रेणी में सभी फ्लैट बुक हो पाए हैं। नोएडा प्राधिकरण (Noida Authority) ने 'पहले आओ पहले पाओ' के आधार पर फ्लैट बेच रही है। फ्लैटों की बिक्री जल्दी हो पाए इसके लिए खरीदारों को लोकेशन चुनने की छूट भी दी गई है। योजना 31 मार्च तक खुली रहेगी।

एंटी डस्ट कैंपेन के तहत अभी तक 7927 निर्माण स्थलों का निरीक्षण, 63 लाख रुपए का लगाया जुर्माना- गोपाल राय

सुषमा रानी

नई दिल्ली, दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने विंटर एक्शन प्लान को लेकर मंगलवार को दिल्ली सचिवालय में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस बैठक में पर्यावरण विभाग, डीपीसीसी, एमसीडी, एनडीएमसी, डीडीए, राजस्व विभाग, जल बोर्ड, विकास विभाग, दिल्ली पुलिस, डीटीसी, आई एंड एफसी, पीडब्लूडी, आदि विभागों के अधिकारी शामिल रहे। बैठक के दौरान पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ विंटर एक्शन प्लान के 21 बिन्दुओ पर चर्चा की। बैठक में ग्रेप के कार्यान्वयन को लेकर भी विभागों को निर्देश दिए गए। उन्होंने आज बताया कि विंटर एक्शन प्लान के तहत सरकार 6 नवंबर से एक महीने के लिए दिल्ली में एंटी ओपन बर्निंग अभियान शुरू करने जा रही है। इस अभियान के तहत सम्बंधित विभागों की 588 पेट्रोलिंग टीम तैनात की जाएँगी। सरकारी विभागों, आरडब्ल्यूए और निर्माण एजेंसी को निर्देश दिया गया है कि रात की ड्यूटी पर तैनात सिक्योरिटी गार्ड को हीटर उपलब्ध करवाएं।

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि ठंड बढ़ने तथा हवा की गति कम होने के कारण दिल्ली और पास के राज्यों में ए.क्यू.आई. 300 से 400 के बीच में रहा है। वैज्ञानिकों की राय के अनुसार तेजी से तापमान कम हो रहा है और हवा की गति भी काफी कम है। आने वाले 10 दिन दिल्ली के लिए भारी रहने वाले है। इसीलिए प्रदूषण के खिलाफ सभी संबंधित विभागों द्वारा किये गए कार्यों को लेकर आज दिल्ली सचिवालय में समीक्षा बैठक बुलाई गयी। बैठक में विंटर एक्शन प्लान की घोषणा के बाद विभागों द्वारा अभी तक किये गए कार्यों की समीक्षा की गयी और आगे की तैयारी पर चर्चा की गयी। विंटर में खुले में आग जलाने से भी प्रदूषण बढ़ता है इसीलिए सरकार 6 नवंबर से एक महीने के लिए दिल्ली में एंटी ओपन बर्निंग अभियान शुरू करने जा रही है। इस अभियान के तहत सम्बंधित विभागों की 588 पेट्रोलिंग टीम तैनात की जाएँगी। यह सभी टीमें 24 घंटे दिल्ली में ओपन बर्निंग की घटनाओ की निगरानी और उसे रोकने का काम करेंगी।

पर्यावरण मंत्री ने बताया कि एंटी डस्ट अभियान से सम्बंधित टीमों ने अभी तक 7927 निर्माण स्थलों का निरीक्षण किया और निर्माण स्थलों पर जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन पाए जाने पर 428 स्थलों को नोटिस और चालान जारी किया है। साथ ही, 63 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। उन्होंने बताया कि टीम में 13 संबंधित विभागों के अधिकारी शामिल हैं। ये दिल्ली के अंदर अलग-अलग स्थानों पर चल रहे निर्माण स्थलों का निरीक्षण कर रहे हैं और मानदंडों के उल्लंघन पर कार्रवाई कर रहे हैं। सभी टीमों को लगातार निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया है। 68 स्टैटिक एंटी-स्मॉग गन्स को सड़कों और खुले क्षेत्रों में तैनात किया गया ताकि सड़क की धूल को फिर से फैलने से रोका जा सके। 200 मोबाइल एंटी-स्मॉग गन 70 विधान सभा में और हॉटस्पॉट में तैनात किए गए ताकि सड़क पर तथा खुले क्षेत्र में धूल को कम किया जा सके। ऊंची इमारतों के ऊपर भी 146 एंटी-स्मॉग गन लगाई गयी है।

गोपाल राय ने कहा कि पराली की समस्या को समाप्त करने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली के धान के खेतों में पूसा बायो-डीकंपोजर का मुफ्त में छिड़काव करती है, इस बार 5000 एकड़ से ज्यादा खेतों मैं बायो-डीकंपोजर का छिड़काव किया जाएगा। अब तक 3258 एकड़ से ज्यादा खेतों मैं बायो-डीकंपोजर का छिड़काव किया किया गया है। पराली जलाने को रोकने तथा निरीक्षण के लिए 11 टीमों का गठन किया गया। साथ ही दिल्ली के किसानों को संवेदनशील/जागरूक बनाने के लिए प्रशिक्षण के कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। गोपाल राय ने बताया कि वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने को लेकर सरकार ने कई कदम उठाये हैं, अक्टूबर से अब तक 76558 गाड़ी का चालान किया गया है। साथ ही 3248 पुराने वाहनों को जब्त किया गया है।

उन्होंने कहा कि सरकारी विभाग, आरडब्ल्यूए, निर्माण एजेंसी को सुरक्षा गार्डों को बिजली के हीटर वितरित करने का निर्देश दिया गया है। ताकि खुले में बायोमास और ठोस अपशिष्ट को जलाने को हतोत्साहित किया जा सके। 500 वर्ग मीटर से ऊपर के निर्माण साइट पर काम करने वाले रात्रि सुरक्षा गार्डों को भी बिजली के हीटर वितरित करने का निर्देश दिया गया है।

सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला स्वागत योग्य: मरकज़ी तालीमी बोर्ड

सुषमा रानी

नई दिल्ली। मरकज़ी तालीमी बोर्ड के सचिव सैयद तनवीर अहमद ने यूपी मदरसा अधिनियम 2004 को बरकरार रखने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है।

मीडिया को जारी एक बयान में बोर्ड के सचिव ने कहा, रहम यूपी मदरसा शिक्षा अधिनियम को बरकरार रखने वाले सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले का स्वागत करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस फैसले को पलट दिया है जिसमें इस अधिनियम को असंवैधानिक घोषित किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक समुदायों के शैक्षिक अधिकारों को बरकरार रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय न केवल मदरसा छात्रों के शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार की रक्षा करता है, बल्कि उन संवैधानिक सिद्धांतों की भी पुष्टि करता है जो धार्मिक अल्पसंख्यकों और उनके शैक्षणिक संस्थानों की रक्षा करते हैं। यह फैसला राज्य के सकारात्मक दायित्व को मजबूत करता है कि इन संस्थानों को अपनी पहचान से समझौता किए बिना धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष दोनों तरह की शिक्षा प्रदान करने में सक्षम बनाया जाए"

सैयद तनवीर ने आगे कहा, रहम मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की माननीय पीठ से सहमत हैं, जिन्होंने इस बात पर जोर दिया कि धर्मनिरपेक्षता का संवैधानिक सिद्धांत यह है कि विधायी ढांचे के भीतर धार्मिक प्रशिक्षण या शिक्षा को शामिल करने मात्र से वह असंवैधानिक नहीं हो जाता। सर्वोच्च न्यायालय ने सही ढंग से दृढ़तापूर्वक स्पष्ट किया है कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है "जीना और जीने देना", तथा भारत के बहुलवादी समाज में विविध शैक्षिक दृष्टिकोणों के सामंजस्यपूर्ण सह-अस्तित्व को बढ़ावा देना। मरकजी तालीमी बोर्ड का मानना है कि निर्णय में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया है जैसे (ए) न्यायालय ने पुष्टि की कि मदरसा अधिनियम मदरसों में शिक्षा को मानकीकृत करने के राज्य के कर्तव्य के अनुरूप है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि छात्र योग्यता के स्तर को प्राप्त करें जिससे सामाजिक भागीदारी और आर्थिक आजीविका सक्षम हो सके।(बी) धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों के अनुरूप अनुच्छेद 21ए और शिक्षा का अधिकार अधिनियम की व्याख्या करके, सर्वोच्च न्यायालय ने इस सिद्धांत को बरकरार रखा कि मदरसे अपने धार्मिक चरित्र को बनाए रखते हुए धर्मनिरपेक्ष शिक्षा प्रदान कर सकते हैं।"

निर्णय की व्यापक प्रासंगिकता पर टिप्पणी करते हुए बोर्ड के सचिव ने कहा, "उत्तर प्रदेश मदरसा अधिनियम को बरकरार रखते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने पुष्टि की है कि ऐसे संस्थान हमारे समाज में सार्थक योगदान देते हैं, और यह निर्णय उन सभी शैक्षणिक संस्थानों को एक आश्वस्त करने वाला संदेश देता है, जिनका उद्देश्य अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान को संरक्षित करना है। यह संतुलित और न्यायसंगत निर्णय उत्तर प्रदेश के लगभग 17 लाख मदरसा छात्रों की आकांक्षाओं को पूरा करने में मदद करेगा तथा उनके सांस्कृतिक मूल्यों और संवैधानिक अधिकारों के ढांचे के भीतर शैक्षिक सशक्तिकरण के उनके अधिकार को मजबूत करेगा। हम आशा करते हैं कि यह निर्णय कुछ एजेंसियों द्वारा चलाए जा रहे उस दुष्प्रचार अभियान को समाप्त कर देगा जो मदरसों की छवि को धूमिल करने तथा मदरसों और आरटीई (शिक्षा का अधिकार) के बीच गलत विभाजन पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं।""

– :सौजन्य :–
ईवी ड्राइव द फ्यूचर
EV
Drive the Future

वाराणसी में ई-रिक्शा के पंजीयन पर रोक व संचालन को लेकर याचिका दाखिल

परिवहन विशेष न्यूज

वाराणसी में ई-रिक्शा के रजिस्ट्रेशन पर रोक और इनके संचालन को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है। याचिका में वाराणसी के जिलाधिकारी (डीएम) द्वारा जारी किए गए आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें ई-रिक्शा के पंजीयन पर रोक लगा दी गई थी और जाम की समस्या के मद्देनजर इनके संचालन पर भी प्रतिबंध लगाया गया था।

हाईकोर्ट की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई के बाद राज्य सरकार और प्रशासन से जवाब तलब किया है। चीफ जस्टिस अरुण भंसाली और जस्टिस विकास बुधवार की खंडपीठ ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए 29 नवंबर को अगली तारीख तय की है।

अखिल भारतीय रिक्शा चालक संघ और अन्य की तरफ से दाखिल याचिका में कहा गया है कि जिलाधिकारी का आदेश मोटर वाहन अधिनियम के खिलाफ है। याचिका में यह भी दावा किया गया कि ई-रिक्शा संचालन से जुड़ी अधिकांश श्रमिक गरीब और निम्न वर्ग के लोग हैं।

जो लोग इस व्यवसाय से अपनी जीविका चला रहे हैं। ऐसे में डीएम का आदेश न केवल अव्यवहारिक है, बल्कि असंवैधानिक भी है, क्योंकि बिना उचित कारण के ई-रिक्शा के पंजीकरण पर रोक लगाना न्यायसंगत नहीं है।

इस मामले में सुनवाई 29 नवंबर को फिर से होगी, जब कोर्ट मामले के सभी पहलुओं पर विस्तृत सुनवाई करेगा। फिलहाल, ई-रिक्शा चालकों और संगठनों को न्याय की उम्मीद है।

चीन ने यूरोपीय संघ के इलेक्ट्रिक कार टैरिफ पर डब्ल्यूटीओ में दर्ज कराई शिकायत

परिवहन विशेष न्यूज

चीन ने यूरोपीय संघ द्वारा चीनी इलेक्ट्रिक वाहनों के आयात पर टैरिफ लगाए जाने के खिलाफ विश्व व्यापार संगठन यानी डब्ल्यूटीओ में शिकायत दर्ज कराई है। जिससे विवाद और बढ़ गया है और पहले से ही तनावपूर्ण संबंधों में और तनाव पैदा हो गया है।

वाणिज्य मंत्रालय के एक बयान के अनुसार बीजिंग ने ईवी उद्योग के ₹विकास हितों की रक्षा₹ के लिए सोमवार को डब्ल्यूटीओ के विवाद निपटान तंत्र में मामला उठाया। मंत्रालय ने यूरोपीय संघ के टैरिफ के प्रति अपने कड़े विरोध को दोहराया और इन शुल्कों की आलोचना ₹व्यापार संरक्षणवाद₹ के रूप में की।

चीन की औपचारिक शिकायत से 2023 में द्विपक्षीय वस्तु व्यापार में 739 अरब यूरो (806 अरब डॉलर) के मूल्य वाले संबंधों में और ज्यादा टकराव का खतरा बढ़ गया है। ब्लॉक ने टैरिफ का बचाव करते हुए कहा है कि यह चीनी सरकार की सब्सिडी की जांच का एक उप-उत्पाद है जो इस क्षेत्र को अनुचित रूप से लाभ पहुंचाता है।

मंत्रालय के प्रवक्ता ने बयान में कहा, ₹चीन का मानना है कि सब्सिडी विरोधी उपायों पर यूरोपीय संघ के अंतिम फैसले में तथ्यात्मक और कानूनी आधार का अभाव है। यह विश्व व्यापार संगठन के नियमों का उल्लंघन करता है और व्यापार उपचार उपायों का दुरुपयोग है।₹ ₹हम यूरोपीय संघ से अपनी गलतियों का सामना करने और अपनी अवैध प्रथाओं को

तुरंत सुधारने और वैश्विक इलेक्ट्रिक वाहन आपूर्ति श्रृंखला और चीन-यूरोपीय संघ आर्थिक और व्यापार सहयोग की स्थिरता को संयुक्त रूप से बनाए रखने का आग्रह करते हैं।"

महीनों की बातचीत, प्रतिशोध की धमकियों और ऑटो उद्योग की पैरवी के बाद यूरोपीय संघ ने पिछले सप्ताह अपने आधिकारिक जर्नल में चीनी ईवी आयात पर 45 प्रतिशत तक के टैरिफ लगाने वाले विनियमन को प्रकाशित किया, जो जुलाई से अनंतिम रूप से प्रभावी हो गया है।

यूरोपीय संघ और उसके दूसरे सबसे बड़े वस्तु-व्यापार साझेदार ने टैरिफ लागू होने के बाद भी वैकल्पिक समाधान तलाशने के लिए चर्चा की है। लेकिन अब तक उन वार्ताओं से कोई सफलता नहीं मिली है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पिछले हफ्ते ब्लॉक ने अधिक बातचीत के लिए अधिकारियों को बीजिंग भेजने का फैसला किया है। दोनों पक्ष इस बात की खोज कर रहे हैं कि क्या तथाकथित मूल्य उपक्रमों पर कोई समझौता किया जा सकता है। यह कीमतों और निर्यात की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए एक जटिल तंत्र है। जिसका उपयोग टैरिफ से बचने के लिए किया जाता है। ब्रुसेल्स और बीजिंग दोनों ने संकेत दिया है कि मतभेद महत्वपूर्ण बने हुए हैं।

यूरोपीय संघ के भावी व्यापार प्रमुख मारोस सेफ्कोविक ने सोमवार, 04 नवंबर को अपनी पुष्टिकरण सुनवाई के दौरान पुष्टि की है कि अधिकारियों का एक दल चीन में है, जो टैरिफ के मुद्दे पर बातचीत के जरिए समाधान ढूंढने की कोशिश कर रहा है।

उन्होंने कहा, ₹हमें व्यापार युद्धों में कोई रुचि नहीं है।" उन्होंने यह भी कहा कि उन क्षेत्रों में बीजिंग के साथ द्विपक्षीय संबंधों को फिर से संतुलित करने की जरूरत है। जहां यूरोप को लगता है कि संबंध उचित नहीं हैं।

यूरोपीय आयोग यूरोपीय संघ की कार्यकारी शाखा है। इसने कहा है कि वह चीन के साथ कई मुद्दों पर चर्चा करना चाहता है। जिनमें महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अत्यधिक क्षमता और यूरोपीय कंपनियों की उसके खरीद बाजार तक पहुंच शामिल है।

देश में ईवी चार्जिंग बाजार 2030 तक 31000 करोड़ रुपये के पार

परिवहन विशेष न्यूज

इलेक्ट्रिक वाहनों के बढ़ते उपयोग के साथ भारत के ईवी चार्जिंग बाजार में तेजी से वृद्धि होने की उम्मीद है। मंगलवार, 05 नवंबर को जारी एक नई रिपोर्ट के अनुसार भारत का ईवी चार्जिंग बाजार 2030 तक 3.7 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा। वैश्विक बाजार में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बाजार के बढ़ने की उम्मीद है। 2030 में इसका राजस्व 164 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। 2023 में यह 25.9 बिलियन डॉलर था, जो लगभग 12 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) दर्शाता है।

प्रमुख तकनीक-सक्षम बाजार खुफिया फर्म 1 लैटिस की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में यह वृद्धि दर 16 प्रतिशत सीएजीआर रहने की उम्मीद है और पर्यावरण संबंधी चिंताओं और ईंधन की कीमतों में उतार-चढ़ाव के कारण इलेक्ट्रिक वाहनों का बढ़ता चलन इस वृद्धि में योगदान देने वाला एक प्रमुख कारक है।

1 लैटिस के औद्योगिक सामान और सेवाओं के निदेशक अभिषेक मैती ने कहा कि भारत का ईवी बाजार 2030 तक 3.7 बिलियन डॉलर तक पहुंचने वाला है, ऐसे में फास्ट-चार्जिंग तकनीक और बैटरी-स्वैपिंग समाधान रेंज की चिंता को दूर करने और ईवी को रोजमर्रा के उपयोगकर्ताओं के लिए अधिक व्यावहारिक बनाने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

भारत में बैटरी स्वैपिंग एक लोकप्रिय समाधान के रूप में उभर रहा है, खासकर दोपहिया और तिपहिया वाहनों के लिए। प्रमुख ऑटो कंपनियां इलेक्ट्रिक वाहनों को अधिक किफायती और सुलभ बनाने के लिए बैटरी-स्वैपिंग तकनीक में निवेश कर रही हैं।

रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक स्तर पर, ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश 2018 और 2023 के बीच लगभग 30 प्रतिशत की सीएजीआर से बढ़ा है। इसी अवधि के दौरान भारत में भी 35 प्रतिशत की सीएजीआर के साथ मजबूत निवेश वृद्धि देखी गई है। पिछले महीने के अंत में एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स की एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार भारत सरकार देश में अधिक ईवी उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखला के अधिक स्थानीयकरण पर जोर दे रही है, जिससे देश को 2030 तक 30 प्रतिशत ईवी लक्ष्य तक पहुँचने में मदद मिलेगी।

सरकार ने हाल ही में दो वर्षों की अवधि में 10,900 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एन्हांसमेंट (पीएम ई-ड्राइव) योजना शुरू की है। पीएम ई-ड्राइव योजना ईवी अपनाने में तेजी लाने और देश भर में महत्वपूर्ण चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, जिससे हमारे पर्यावरण को स्वच्छ बनाने में मदद मिलेगी।

होंडा ने पेश किया इलेक्ट्रिक स्कूटर, कॉन्सेप्ट ई-बाइक की भी दिखाई झलक

परिवहन विशेष न्यूज

आइकमा 2024 में होंडा ने इलेक्ट्रिक स्कूटर पेश करने के साथ ही दो e-Bike कॉन्सेप्ट को भी पेश किया है। इलेक्ट्रिक स्कूटर एक बार फुल चार्ज होने के बाद 70 किमी से ज्यादा का रेंज देगा। वहीं concept electric bike बाइक की बात करें तो यह फुल चार्ज होने के बाद 100 किमी से ज्यादा का रेंज देंगी।

नई दिल्ली। पिछले साल हुए EICMA में होंडा कंपनी ने अपनी कई गाड़ियों को पेश किया था। उसी तरह इस साल भी कंपनी अपने कई प्रोडक्ट को पेश कर रही है। इस बार कंपनी ने इलेक्ट्रिक स्कूटर और कॉन्सेप्ट बाइक की एक सीरीज दिखाई। इसमें से ई-स्कूटर जल्द ही ग्लोबल लेवल पर लॉन्च हो सकता है। आइए जानते हैं इनके बारे में।

CUV e इलेक्ट्रिक स्कूटर पिछले साल पेश हुई EM 1e के बाद होंडा कंपनी की लाइनअप में शामिल होने वाला दूसरा ईवी है। होंडा की इस electric scooter को पावर देने के लिए दो रिमूवेबल बैटरी पैक का इस्तेमाल किया गया है। कंपनी की तरफ से इसकी रेंज को लेकर कहा गया है यह एक बार फुल चार्ज होने के बाद इससे 70 किमी से अधिक तक का सफर तय किया जा सकता है। इस मॉडल का कॉन्सेप्ट पिछले साल टोक्यो मोटर शो में भी दिखाया गया था।

होंडा CUV e दो डिस्प्ले ऑप्शन के साथ आ सकती है, जो या तो 5-इंच वाला या ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाला 7-इंच TFT डिस्प्ले होगा। इसमें 3 राइडिंग मोड स्टैंडर्ड, स्पोर्ट और इको देखने के लिए मिलेंगे और साथ ही यह रिवर्स फंक्शन वाला फीचर्स भी होगा।

EV फन कॉन्सेप्ट होंडा की स्पोर्टी इलेक्ट्रिक नेकेड

बाइक बनाने जा रही है। जिसका कॉन्सेप्ट वर्जन EICMA 2024 में पेश किया गया है। इस बाइक को लेकर कंपनी का दावा है कि उनकी यह इलेक्ट्रिक बाइक फ्यूल से चलने वाली बाइक के बराबर ही परफॉर्म करेगी। इसे साल 2025 में लॉन्च किया जाएगा।

भले ही इसके कॉन्सेप्ट स्टेज को पेश किया गया है, लेकिन इसमें दिखाई दिए ब्रेक और सस्पेंशन से यह संकेत मिलता है यह डेवलपमेंट के आखिरी स्टेज पर है।

कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक बाइक का डिजाइन स्पोर्टी नेकेड जैसा है। इसमें सिंगल-साइडेड स्विंगआर्म का शानदार टच दिया गया है। इसमें दी गई हेडलाइट, ओला रोडस्टर इलेक्ट्रिक बाइक लाइनअप से काफी मेल खाती है।

होंडा की यह concept electric bike की बैटरी CCS2 क्विक चार्जर के साथ आ सकती है, जिससे चार्जिंग के ज्यादा ऑप्शन खुलेंगे। कंपनी इस बाइक को लेकर दावा कर रही है कि यह फुल चार्ज होने के बाद 100 किमी से ज्यादा की रेंज देगी।

ईवी फन कॉन्सेप्ट बाइक के विपरीत ईवी अर्बन कॉन्सेप्ट को भी लॉन्च होने में काफी समय है। अभी तक इसके पावरट्रेन या अंडरपिनिंग की कोई डिटेल्स सामने नई आई है। इसका डिजाइन काफी हद तक BMW CE 04 जैसा देखने के लिए मिला है, जो एक प्रीमियम इलेक्ट्रिक स्कूटर है। जिसकी वजह से होंडा की EV अर्बन कॉन्सेप्ट में BMW CE 04 जैसी चीजें देखने के लिए मिल सकती है।

मारुति सुजुकी लेकर आई अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार

परिवहन विशेष न्यूज

मारुति सुजुकी अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार लेकर आई है। जापानी कार निर्माता कंपनी ने ग्लोबल मार्केट में अपनी पहली ईवी ई-विटारा की झलक दिखाई है। मारुति ने इस गाड़ी को इटली के मिलान में आयोजित मोटर शो में दिखाया था। वहीं मारुति ने भारत में आयोजित ऑटो एक्सपो में इसके प्रोडक्शन स्पेक वर्जन eVX कॉन्सेप्ट को पहले ही पेश कर दिया है। ई-विटारा को भारत में किसी और नाम से लाया जा सकता है, लेकिन इस गाड़ी का बेसिक कॉन्सेप्ट लुक 4 मीटर की एसयूवी से भी बड़ा होगा। यह गाड़ी 4,275 mm की लंबाई के साथ आने वाली है।

मारुति ई-विटारा का लुक ग्रैंड विटारा से काफी अलग है। यह इलेक्ट्रिक कार Heartect e-प्लेटफॉर्म पर आधारित है। इस गाड़ी के फ्रंट में शार्प DRLs हैं, ब्लैंक्ड ऑफ ग्रिल लगाई गई है। इस इलेक्ट्रिक कार के टॉप-एंड वर्जन में 19 इंच के अलॉय व्हील का इस्तेमाल किया गया है। वहीं इसके स्टैंडर्ड प्लस वेरिएंट में 18 इंच के अलॉय व्हील लगाए गए हैं। मारुति ई-विटारा में पिछली स्विफ्ट में लगे डोर हैंडल लगाए गए हैं।

वैश्विक बाजार में पेश की गई मारुति की ईवी का इंटीरियर काफी स्पेशियस है। मारुति ई-विटारा में डैशबोर्ड का डिजाइन अलग रखा गया है। इस कार में नया 2-स्पोक स्टीयरिंग व्हील दिया गया है। इसमें ट्विन स्क्रीन लेआउट है और नया ड्राइव सिलेक्टर भी दिया गया है। मारुति की इस इलेक्ट्रिक कार में 2700 एमएम का व्हील बेस भी दिया गया है।

मारुति ई-विटारा के स्टैंडर्ड वर्जन में सिंगल फ्रंट मोटर है, जिसमें 49 kWh का बैटरी पैक है। यह 142 bhp की पावर देता है और 189 Nm का टॉर्क जेनरेट करता है। मारुति की यह इलेक्ट्रिक कार बड़े बैटरी पैक के साथ भी आती है। इस कार में 61 kWh के बैटरी पैक के साथ डुअल मोटर है, जो 180 bhp की पावर और 300 Nm का टॉर्क देता है।

जापानी ऑटोमेकर की इलेक्ट्रिक कार का प्रोडक्शन भारत में साल 2025 में सुजुकी मोटर गुजरात में किया जा सकता है। यह कार नेक्सा सेल्स आउटलेट्स के साथ आ सकती है। यह मारुति की सबसे प्रीमियम कार हो सकती है। मारुति की यह इलेक्ट्रिक कार टाटा कर्व ईवी, महिंद्रा बीई और हुंडई क्रेटा ईवी को कड़ी टक्कर दे सकती है।

महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी ने अब तक 2 लाख से ज़्यादा कमर्शियल इलेक्ट्रिक वाहन बेचे

परिवहन विशेष न्यूज

महिंद्रा एंड महिंद्रा की सहायक कंपनी महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी लिमिटेड ने मंगलवार, 05 नवंबर को कहा कि उसने अब तक 2 लाख से ज़्यादा कमर्शियल इलेक्ट्रिक वाहन बेचे हैं।

पिछले 17 महीनों में महिंद्रा ने 1 लाख से ज़्यादा EV बेचे हैं, जिसमें ट्रिओ प्लस, ई-अल्फ़ा प्लस और महिंद्रा जियो जैसे नए तकनीकी रूप से उन्नत उत्पाद लॉन्च किए गए हैं।

सियाम के आंकड़ों के अनुसार एल5 श्रेणी में महिंद्रा की बाजार हिस्सेदारी 41.2 प्रतिशत है।

महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी के प्रबंध निदेशक और सीईओ सुमन मिश्रा ने कहा ₹हमारे सहयोगी, चुस्त और साहसिक प्रयासों ने विश्वसनीय उत्पादों और एकीकृत समाधानों के साथ लास्ट माइल इकोसिस्टम को फिर से कल्पित करने में मदद की है। 2,00,000 इलेक्ट्रिक वाहनों के मील के पत्थर तक पहुँचना नवाचार के प्रति हमारे समर्पण और शहरी रसद की उभरती जरूरतों को संबोधित करने को दर्शाता है।"

महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी के लाइनअप में महिंद्रा ट्रिओ रेंज, ई-अल्फा रेंज और ज़ोर ग्रैंड श्री-व्हीलर शामिल हैं। कंपनी ने हाल ही में महिंद्रा जियो एक इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर स्मॉल कमर्शियल व्हीकल के लॉन्च के साथ अपने पोर्टफोलियो का विस्तार किया है।

वाहन डेटा के अनुसार महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी ने श्री-व्हीलर एल5 सेगमेंट को इलेक्ट्रिक बनाने में महत्वपूर्ण प्रगति की है, जिसमें वित्त वर्ष 2025 (वर्ष-दर-वर्ष) में इस श्रेणी में कुल 21.7 प्रतिशत पैठ है।

कंपनी ने कहा कि बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए, बेंगलुरु, हरिद्वार और ज़हीराबाद में महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी के विश्व स्तरीय विनिर्माण संयंत्रों में उत्पादन में भी काफी वृद्धि की गई है।

कंपनी ने एक नया लॉयल्टी प्रोग्राम भी पेश किया है, जिसके तहत जो लोग महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी का नया वाहन खरीदेंगे, उन्हें 20 लाख रुपये का ड्राइवर दुर्घटना बीमा कवर मिलेगा, साथ ही ग्राहकों के बच्चों के लिए करियर काउंसलिंग, व्यवसाय/वित्त परामर्श और बहुत कुछ मिलेगा।

इस बीच सितंबर में भारत में कुल ईवी पंजीकरण 1.59 लाख यूनिट तक पहुँच गया, जो पिछले साल इसी महीने 1.29 लाख यूनिट था।

चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में सभी खंडों में कुल ईवी पंजीकरण पिछले वर्ष की समान अवधि के 7.45 लाख यूनिट की तुलना में बढ़कर 8.93 लाख यूनिट हो गया।

ईवी अपनाने को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एन्हांसमेंट (पीएम ई-ड्राइव) योजना शुरू की है, जिसका वित्तीय परिव्यय दो वर्षों की अवधि में 10,900 करोड़ रुपये है।

अदृश्य जंजीरें: डिजिटल युग में इंटरनेट की लत

विजय गर्ग

आज की हाइपर-कनेक्टेड दुनिया में, इंटरनेट दैनिक जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा बन गया है, जो हमारे काम करने, सीखने, मेलजोल और मनोरंजन करने के तरीके को नया आकार देता है। जबकि डिजिटल कनेक्टिविटी कई लाभ प्रदान करती है, यह इंटरनेट की लत के खतरे को भी पेश करती है - एक बढ़ती हुई समस्या जो दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित कर रही है, जिसके मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक कल्याण पर गंभीर परिणाम हो रहे हैं। जैसे-जैसे इंटरनेट का उपयोग हमारे जीवन में अधिक शामिल होता जा रहा है, इसकी जटिलताओं को समझना और ऑनलाइन जुड़ाव के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण ढूंढना पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। इंटरनेट की लत, या समस्याग्रस्त इंटरनेट उपयोग (पीआईयू), ऑनलाइन अत्यधिक समय बिताने की अनिवार्य आवश्यकता को संदर्भित करता है, अक्सर वास्तविक जीवन की जिम्मेदारियों, रिश्तों और व्यक्तिगत भलाई की कीमत पर। यह व्यवहार विभिन्न रूपों में प्रकट हो सकता है, जैसे बाध्यकारी सोशल मीडिया ब्राउज़िंग, ऑनलाइन गेमिंग, शॉपिंग, स्ट्रीमिंग, या सामग्री उपभोग। हालाँकि इंटरनेट की लत को आधिकारिक तौर पर सभी डायग्नोस्टिक मैनुअल में एक नैदानिक विकार के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है, लेकिन यह मान्यता प्राप्त व्यवहारिक व्यसनों के साथ विशेषताओं को साझा करता है और मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों द्वारा इसे वास्तविक मानसिक स्वास्थ्य चिंता के रूप में तेजी से स्वीकार किया जा रहा है। न्यूरोलॉजिकल स्तर पर, इंटरनेट की लत पदार्थ और व्यवहारिक व्यसनों में देखे गए प्रभावों को प्रतिबिंबित करती है। डोपामाइन रिलीज द्वारा सक्रिय मस्तिष्क की इनाम प्रणाली, आनंद प्रतिक्रियाएं पैदा करके दोहराव वाले व्यवहार को मजबूत करती है। उपयोगकर्ताओं को जोड़े रखने के लिए डिज़ाइन की गई इंटरनेट-आधारित गतिविधियाँ, निर्भरता को बढ़ावा देने के लिए इस फीडबैक लूप का लाभ उठाती हैं। समय के साथ, व्यक्ति तनाव, ऊब या नकारात्मक भावनाओं से निपटने के साधन के रूप में ऑनलाइन जुड़ाव की तलाश शुरू कर देते हैं, जिसके परिणामस्वरूप निर्भरता पैदा होती है जो दैनिक कामकाज में हस्तक्षेप करती है। इंटरनेट की लत के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव इंटरनेट की लत मानसिक स्वास्थ्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती है, सामान्य दिनचर्या को बाधित कर सकती है, सामाजिक संपर्क को कमजोर कर सकती है और उत्पादकता को कम कर सकती है। अनुसंधान ने अत्यधिक इंटरनेट उपयोग को चिंता, अवसाद और कम आत्मसम्मान से जोड़ा है, क्योंकि व्यक्ति वास्तविक दुनिया के अनुभवों और व्यक्तिगत विकास की कीमत पर ऑनलाइन गतिविधियों में लीन हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त, ऑनलाइन सामग्री की निरंतर उपलब्धता से डिजिटल अधिभार, या ₹सूचना थकान₹ की भावना पैदा हो सकती है, जो उपयोगकर्ताओं को मानसिक रूप से थका हुआ और अभिभूत महसूस कराती है। इन मानसिक स्वास्थ्य प्रभावों का एक प्रमुख चालक सोशल मीडिया है, जो अक्सर वास्तविकता के एक आदर्श संस्करण को बढ़ावा देता है। इंस्टाग्राम और टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म सावधानी से तैयार की गई छवियां पेश करते हैं जो संपूर्ण शरीर, शानदार जीवन शैली और अंतहीन खुशी का प्रदर्शन करती हैं। जो लोग पहले से ही आत्मसम्मान के साथ संघर्ष कर रहे हैं, उनके लिए आदर्श सामग्री की यह स्थिर धारा एक विषाक्त ₹तुलना और निराशा₹ मानसिकता को बढ़ावा दे सकती है, जहां उपयोगकर्ता इन विकृत छवियों के खिलाफ अपने आत्म-मूल्य को मापते हैं। अध्ययनों से पता चला है कि जो उपयोगकर्ता सोशल मीडिया पर महत्वपूर्ण समय बिताते हैं, उनमें अवसाद, अपर्याप्तता की भावना और अपने जीवन से असंतोष का अनुभव होने की संभावना अधिक होती है। डिजिटल बर्नआउट: लगातार कनेक्टिविटी का परिणाम इंटरनेट की लत का एक महत्वपूर्ण परिणाम डिजिटल बर्नआउट है। जैसे-जैसे इंटरनेट की लत बढ़ती है, मस्तिष्क, ऑनलाइन जानकारी के निरंतर प्रवाह के संपर्क में आने पर, थकान का अनुभव करता है, जो कम ध्यान देने की अवधि, बिगड़ा हुआ संज्ञानात्मक कार्य और मानसिक थकावट की व्यापक भावना के रूप में प्रकट होता है। यह मानसिक थकान उत्पादकता को कम कर सकती है और निर्णय लेने को जटिल बना सकती है। विशेष रूप से डिजिटल बर्नआउट हैदूरदराज के श्रमिकों, छात्रों और ऐसे व्यक्तियों के बीच आम है जिनका काम ऑनलाइन जुड़ाव पर बहुत अधिक निर्भर करता है। एक ही स्क्रीन पर काम, सामाजिक जीवन और मनोरंजन का मिश्रण जिम्मेदारियों के बीच की सीमाओं को धुंधला कर देता है, जिससे काम के घंटों के बाहर भी ₹स्विच ऑफ₹ करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। समय के साथ, डिजिटल बर्नआउट जीवन की गुणवत्ता को कम कर देता है और दीर्घकालिक तनाव और चिंता जैसे अधिक गंभीर मानसिक स्वास्थ्य मुद्दों को जन्म दे सकता है। किशोर: एक विशेष रूप से कमजोर जनसांख्यिकीय किशोर

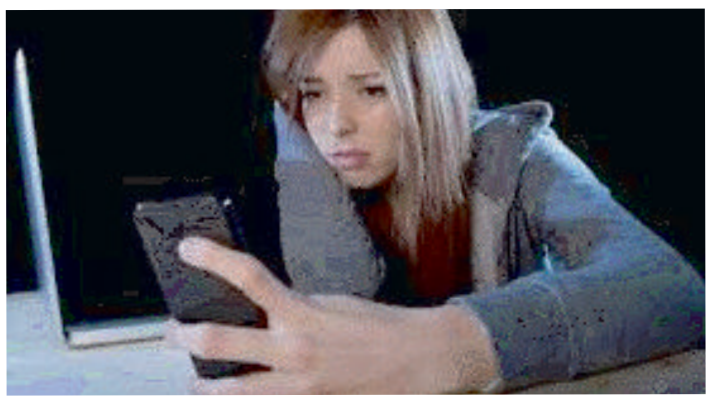

विशेष रूप से इंटरनेट की लत के प्रति अतिसंवेदनशील होते हैं। ऐसे माहौल में पले-बढ़े जहां प्रौद्योगिकी सामान्यीकृत है, आज के युवा डिजिटल मूल निवासी हैं जो लगातार जुड़े रहते हैं।

जबकि यह कनेक्टिविटी शैक्षिक और सामाजिक लाभ लाती है, यह ऑनलाइन निर्भरता के प्रति उनकी संवेदनशीलता को भी बढ़ाती है। इंटरनेट के आदी किशोरों को अक्सर शैक्षणिक गिरावट, सामाजिक अलगाव और ऑफ़लाइन गतिविधियों में कम भागीदारी का अनुभव होता है। ऑनलाइन गेमिंग युवाओं में इंटरनेट की लत की सबसे आम अभिव्यक्तियों में से एक है। कई गेम उपयोगकर्ताओं को पुरस्कारों, सामाजिक संपर्कों और आभासी उपलब्धियों से जोड़े रखने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं जो विस्तारित खेल सत्रों को प्रोत्साहित करते हैं। कुछ लोगों के लिए, यह व्यवहार गेमिंग विकार की ओर ले जाता है, जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) द्वारा आधिकारिक तौर पर एक मानसिक स्वास्थ्य स्थिति के रूप में मान्यता दी गई है। लंबे समय तक गतिहीन व्यवहार के कारण गेमिंग विकार शिक्षा, पारिवारिक रिश्तों और शारीरिक स्वास्थ्य को बाधित कर सकता है। किशोरों के लिए चिंता का एक अन्य क्षेत्र सोशल मीडिया की लत है। छवि-साझाकरण, स्थिति अपडेट और त्वरित प्रतिक्रिया पर जोर देने के साथ, सोशल मीडिया एक प्रदर्शनकारी संस्कृति को प्रोत्साहित करता है जहां उपयोगकर्ता अपने जीवन के हर पहलू का दस्तावेजीकरण करने के लिए मजबूर महसूस करते हैं। ऑनलाइन दर्शकों के लिए ₹प्रदर्शन₹ करने की यह निरंतर आवश्यकता अस्वास्थ्यकर आत्म-छवि संबंधी समस्याएं पैदा कर सकती है, जिससे चिंता, अवसाद और शारीरिक डिस्मोर्फिया जैसी मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों का खतरा बढ़ सकता है। इंटरनेट की लत के सामाजिक प्रभाव इंटरनेट की लत का विरोधाभास कनेक्शन की भावना में निहित है जो व्यक्तियों को वास्तविक सामाजिक संपर्क से अलग करता है। सोशल मीडिया, मैसेजिंग ऐप और ऑनलाइन समुदाय संचार के रास्ते उपलब्ध कराते हैं, फिर भी उपयोगकर्ता अक्सर पहले की तुलना में अकेलापन महसूस करते हैं। ऑनलाइन बनाए गए संबंध, हालांकि तत्काल और सुलभ होते हैं, अक्सर सतही होते हैं और उनमें व्यक्तिगत संबंधों की भावनात्मक गहराई का अभाव होता है। जैसे-जैसे व्यक्ति अपने ऑनलाइन जीवन में अधिक लीन हो जाते हैं, वे वास्तविक दुनिया के रिश्तों की उपेक्षा करने का जोखिम उठाते हैं जो भावनात्मक समर्थन और संतुष्टि प्रदान करते हैं। शोध से पता चला है कि इंटरनेट के आदी लोगों को सामाजिक अलगाव का अनुभव होने की अधिक संभावना है और उन्हें सार्थक रिश्ते बनाने और बनाए रखने में कठिनाई होती है। इससे अकेलेपन की भावनाएं बढ़ सकती हैं, जो इन भावनाओं से बचने के साधन के रूप में इंटरनेट पर निर्भरता को और मजबूत कर सकती है। इंटरनेट की लत के लक्षणों को पहचानना इंटरनेट की लत से निपटने के लिए जागरूकता पहला कदम है। सामान्य संकेतों में शामिल हैं: अक्सर व्यक्तिगत ज़िम्मेदारियों की कीमत पर, अपनी इच्छा से अधिक समय ऑनलाइन बिताना। इंटरनेट पर व्यस्तता: ऑफ़लाइन होने पर भी ऑनलाइन गतिविधियों के बारे में सोचना। शारीरिक स्वास्थ्य की उपेक्षा: इंटरनेट के उपयोग के पक्ष में नींद और व्यायाम जैसी बुनियादी जरूरतों को नजरअंदाज करना। नकारात्मक भावनाओं से बचने या तनाव से निपटने के लिए इंटरनेट का उपयोग करना। इंटरनेट का उपयोग करने में असमर्थ होने पर चिंतित, चिड़चिड़ापन या बेचैनी महसूस करना। इन संकेतों को पहचानना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह व्यक्तियों को अपने जीवन में इंटरनेट की भूमिका का आकलन करने की अनुमति देता हैऔर स्वस्थ डिजिटल आदतों की दिशा में सक्रिय कदम उठाएं। इंटरनेट की लत से मुकाबला: स्वस्थ जुड़ाव के लिए रणनीतियाँ इंटरनेट की लत को प्रबंधित करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है जो पेशेवर मार्गदर्शन के साथ व्यक्तिगत अनुशासन को संतुलित करता है। बाध्यकारी व्यवहार को कम करने में मदद के लिए इंटरनेट के उपयोग के लिए समय सीमा निर्धारित करना आवश्यक है। जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए डिवाइस और ऐप्स में अक्सर स्क्रीन टाइम को ट्रैक करने के लिए अंतर्निहित टूल होते हैं। पढ़ने, व्यायाम करने और बाहर समय बिताने जैसी ऑफ़लाइन गतिविधियों में शामिल होने से डिजिटल उत्तेजना पर भरोसा किए बिना संतुष्टि मिल सकती है। डिजिटल उपकरणों से समय-समय पर ब्रेक लेने से मस्तिष्क को रीसेट करने में मदद मिल सकती है और डिजिटल बर्नआउट से राहत मिल सकती है। इंटरनेट का उपयोग करते समय सचेतनता का अभ्यास करने से व्यक्तियों को बिना सोचे-समझे स्क्रॉल करने के बजाय जानबूझकर जुड़ाव पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिल सकती है। थेरेपी, विशेष रूप से संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी (सीबीटी), इंटरनेट की लत से जूझ रहे लोगों के लिए मूल्यवान सहायता प्रदान कर सकती है। इंटरनेट की लत के खतरों के बारे में खुली चर्चा को बढ़ावा देने से जागरूकता बढ़ाने और जिम्मेदार इंटरनेट उपयोग को प्रोत्साहित करने में मदद मिल सकती है। डिजिटल संतुलन को अपनाना: इंटरनेट एक शक्तिशाली उपकरण है जो लोगों को जोड़ने, ज्ञान फैलाने और नवाचार को बढ़ावा देने में सक्षम है। हालाँकि, किसी भी उपकरण की तरह, इसका उपयोग समझदारी से किया जाना चाहिए। इंटरनेट की लत को समझकर और संतुलित डिजिटल आदतों की दिशा में सक्रिय रूप से काम करके, हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि इंटरनेट हमारे जीवन को कम करने के बजाय उसे समृद्ध बनाए। लत के लक्षणों को पहचानने, उपयोग को प्रबंधित करने के लिए कदम उठाने और एक स्वस्थ ऑनलाइन संस्कृति की वकालत करने से व्यक्तियों को इंटरनेट की लत की जटिलताओं से निपटने में मदद मिलेगी। ऐसी दुनिया में जहां इंटरनेट कनेक्टिविटी दैनिक जीवन का अभिन्न अंग है, लक्ष्य इंटरनेट के उपयोग को खत्म करना नहीं है बल्कि इसके साथ संतुलित संबंध को बढ़ावा देना है। जैसे-जैसे हम संतुलन के लिए प्रयास करते हैं, हम अपने मानसिक कल्याण, रिश्तों और जीवन की गुणवत्ता को संरक्षित करते हुए इंटरनेट के लाभों का उपयोग कर सकते हैं, जिससे कनेक्टिविटी के युग में एक अधिक संतुष्टिदायक भविष्य का निर्माण हो सके।

आस्था मानव मन की पवित्र भावना है

विजय गर्ग

पूरी दुनिया आस्था पर आधारित है. संसार में सत्य केवल विश्वास पर ही खड़ा है। परिवार का प्रेम, समाज का उत्थान, देश की उन्नति और विश्व का कल्याण सब विश्वास पर ही निर्भर है। विश्वास के बिना, परिवार बिखर जाते हैं। सारे सांसारिक रिश्ते विश्वास की बुनियाद पर टिके हैं। यदि मानव जीवन में आस्था हो तो हर व्यक्ति अपना भविष्य तय कर सकता है। उसे क्या करना है, क्या बनना है, यह विश्वास ही मनुष्य की सोच हैसे उत्पन्न होता है हर समय मानवीय सोच का समर्थन करता है। इसका विकास विचार का विकास है। आस्था के बिना इंसान का अपनी मंजिल तक पहुंचना नामुमकिन है। यह असंभव कार्य को भी संभव बना देता है। आस्था मनुष्य का मार्गदर्शन करती है। विश्वास करके ही मनुष्य ने महान ऊँचाइयाँ प्राप्त की हैं। मनुष्य ने दूसरे ग्रहों पर जाकर इस आशा के साथ शोध जारी रखा कि एक दिन वह सफलता प्राप्त करके लौटेगा। हालाँकि इसके लिए उन्हें कई कुर्बानियाँ देनी पड़ीं। भले ही पीड़ित शारीरिक रूप से ही क्यों न होवे दुनिया से रुखसत हो गए हैं, लेकिन मानव मन में लक्ष्य प्राप्ति के लिए आस्था की धीमी रोशनी छोड़ गए हैं। विश्वास के साथ, मनुष्य ने पहाड़ों को पार किया है, समुद्र में खजाना पाया है, और जहाजों में उड़ान भरी है। केवल विश्वास के साथ ही मनुष्य ने अज्ञानी दुनिया का सामना किया और अकल्पनीय को अस्तित्व में बदल दिया। सभी रिश्ते विश्वास पर टिकते हैं। बच्चों को अपने माता-पिता पर असीमित विश्वास होता है और माता-पिता अपनी बेटियों और बेटों पर विश्वास करते हैं और उपलब्धियों के लिए अवसर और आराम प्रदान करते हैं, जब बच्चे अपने माता-पिता पर निर्भर होते हैं।यदि वे अपना विश्वास तोड़ते हैं और गलत रास्ते पर वापस जाते हैं, तो उनका दिल टूट जाता है। विश्वास से ही पति-पत्नी का वैवाहिक जीवन स्वर्ग

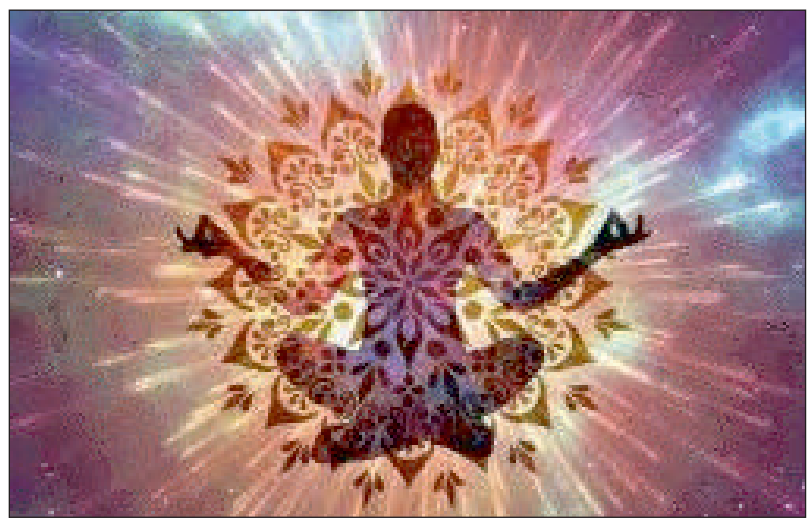

बन जाता है। यदि आस्था में थोड़ी सी भी कमी हो जाए तो हंसता-खेलता परिवार नर्क का रूप धारण कर लेता है। भरोसे के दम पर हम रिश्तों की ज़रूरतें पूरी करते हैं। जब किसी बच्चे को स्कूल में शिक्षक को सौंपा जाता है, तो शिक्षक और छात्र के बीच का रिश्ता विश्वास पर आधारित होता है। आस्था हर पेशे में शामिल है. विश्वासी केवल विश्वास के द्वारा ही तर्क करते हैंसीढ़ियाँ चढ़ना और शीर्ष तक पहुँचना आसान है। संपूर्ण विश्व की सुख-शांति विश्वास पर ही निर्भर है। विश्वास पर आधारित रिश्तों की उम्र लंबी होती है। ईश्वर या प्रकृति प्रेम का दिव्य उपहार है। प्रकृति के साथ एक होने के लिए प्रकृति में विश्वास आवश्यक है। प्रकृति ने मनुष्य पर विश्वास किया और उसे सांस लेने के लिए ऑक्सीजन का उपहार दिया। मनुष्य का भी कर्तव्य है कि वह प्रकृति के प्रति आस्था बनाये रखते हुए भावी पीढ़ियों के लिए ऑक्सीजन का उपहार सुरक्षित रखे। विश्वास को ईश्वर से एकाकार करने के लिए भक्ति के साथ जोड़ा जाता है।तमाम शंकाओं और संदेहों से मनुष्य अस्थिर हो जाता है, जबकि भक्ति और विश्वास से व्यक्ति अतुलनीय क्षमता और स्थिरता प्राप्त करता है। जीवन में उच्च पद, उन्नति और अच्छे कर्म सभी भक्ति और विश्वास के माध्यम से प्राप्त होते हैं। प्रकृति का दिव्य स्वरूप मनुष्य को आध्यात्मिक ज्ञान देता है। मन की स्थिरता के लिए व्यक्ति दैवीय शक्ति का सहारा लेता है और उसका जीवन आनंदमय हो जाता है। आस्था के बिना भक्ति संभव नहीं है और न ही सांसारिकता। आस्था के बिना जीवन के मापदण्ड निर्धारित करना कठिन हो जाता है। अगर हम ध्यान से देखें, संसादुनिया में रहने वाले ज्यादातर लोग भगवान से इसी वजह से जुड़ते हैं ताकि उन्हें सांसारिक सुख मिल सकें। उन पर कोई बुरी घड़ी न आए. वे अपनी मांगों के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। यह प्रार्थना आस्था का एक रूप है. अगर जीवन में कुछ अप्रत्याशित घटित हो जाए तो व्यक्ति का विश्वास डगमगाने लगता है, वह अंधविश्वास की राह पर चलने लगता है। दुनिया में कम ही लोग ऐसे होते हैं. जो लोग ईश्वरीय स्वरूप पर पूर्ण विश्वास रखते हैं और जीवन में हर स्थिति में दृढ़ रहते हैं और उनका दृढ़ विश्वास कभी नहीं होताडगमगाता भी नहीं. मन की गहराई से मन की अच्छी सोच के साथ दृढ़ विश्वासी आस्था की दृढ़ता की ऊंचाइयों को छूते हैं। मनुष्य अपने आत्म-अन्वेषण से ही स्वयं पर भरोसा कर सकता है। बेटियों के माता-पिता विश्वास के सहारे ही अपनी बेटियों को समाज में आगे बढ़ने के लिए भेजते हैं, लेकिन जब समाज में उनके साथ कोई अप्रत्याशित घटना घटती है तो माता-पिता का विश्वास पूरी दुनिया से टूट जाता है। इतिहास के पन्ने पलटने से पता चलता है कि विपरीत परिस्थिति के बावजूद भी धर्म ने आस्था को रास्ता नहीं दिया है। अच्छे लक्ष्यमनुष्य को दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। जब यह मान्यता अंधविश्वास बन जाती है तो मानव मानस रुग्ण हो जाता है। अंधविश्वासी आदमी बिना देखे विश्वास कर लेता है. उसके मन में दूषित भावनाएँ उत्पन्न हो जाती हैं। अंधविश्वास की राह पर चलकर वे आस्था और अंध विश्वास में अंतर नहीं कर पाते। दुनिया के हर रिश्ते, हर काम के लिए भरोसे की ज़रूरत होती है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि कोई भी विश्वास केवल सत्य पर आधारित होता है। सत्य पर आधारित विश्वास ही जीवन भर टिकता है।झूठ, लालच, धोखा और स्वार्थ विश्वास को तोड़ने में देर नहीं लगाते। जब किसी भरोसेमंद इंसान को धोखा मिलता है तो उस सदमे से उबरने में काफी समय लग जाता है। किसी विश्वसनीय पात्र द्वारा धोखा दिया जाना अधिक दर्दनाक है। ईश्वर मानव मन में आस्था की लौ सदैव प्रज्वलित रखे। इस जगदी लो के प्रकाश में मानव मन से विश्वासघात हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा और पूरे विश्व में सुख और शांति का वास होगा।

भारतीय शिक्षा प्रणाली और जॉब मार्केट के बीच गहरा संबंध

भारतीय शिक्षा प्रणाली और जॉब मार्केट के बीच गहरा संबंध है, लेकिन इस संबंध में कई चुनौतियाँ और असंतुलन भी देखने को मिलते हैं। भारतीय शिक्षा प्रणाली में सुधार की आवश्यकता लगातार महसूस की जा रही है ताकि यह बदलते हुए जॉब मार्केट की मांगों के अनुरूप बन सके। यहाँ कुछ प्रमुख बिंदुओं पर विचार किया जा सकता है:

1. थ्योरी और प्रैक्टिकल नॉलेज का अंतर

भारतीय शिक्षा प्रणाली में अधिकतर जोर थ्योरी पर दिया जाता है। हालांकि, वर्तमान जॉब मार्केट में कंपनियों को ऐसे प्रोफेशनल्स की जरूरत होती है, जिनके पास व्यावहारिक ज्ञान हो और वे कार्यक्षेत्र में आसानी से योगदान दे सकें। छात्रों को प्रैक्टिकल नॉलेज देने के लिए इंडस्ट्री-अलायंस, इंटर्नशिप, और प्रोजेक्ट्स पर ध्यान देना जरूरी है।

2. स्किल डिवेलपमेंट की कमी

जॉब मार्केट में सफलता के लिए तकनीकी स्किल्स के साथ-साथ सॉफ्ट स्किल्स, जैसे कम्युनिकेशन, टीम वर्क, और प्रॉब्लम-सॉल्विंग जरूरी हैं। भारतीय शिक्षा प्रणाली में ऐसे कौशलों पर कम जोर दिया जाता है। इसके कारण बहुत से छात्रों में आत्मविश्वास और सही स्किल्स की कमी होती है।

3. अधिक फोकस पारंपरिक कोर्सेज पर

भारतीय शिक्षा प्रणाली में इंजीनियरिंग, मेडिकल और कुछ पारंपरिक कोर्सेज पर अधिक जोर दिया जाता है, जबकि नई तकनीकों और अन्य क्षेत्रों में नौकरी के अवसर बढ़ रहे हैं, जैसे कि डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और डिज़ाइन। ऐसे में करियर विकल्पों में विविधता लाने की जरूरत है ताकि छात्र बदलते समय के अनुसार तैयार हो सकें।

4. रोज़गार के अवसरों की असमानता

कई बार देखा गया है कि बड़ी संख्या में ग्रेजुएट्स जॉब मार्केट में प्रवेश तो कर लेते हैं, लेकिन उनके पास जॉब पाने के लिए आवश्यक कौशल नहीं होते। इसके कारण 'अनइम्प्लॉयमेंट' और 'अंडरइम्प्लॉयमेंट' जैसी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं।

5. शिक्षा नीति में सुधार

नई शिक्षा नीति (NEP 2020) का उद्देश्य इस असंतुलन को कम करना है, जिसमें कौशल विकास, व्यावहारिक शिक्षा, और इंडस्ट्री-रेडी कोर्सेज पर जोर दिया गया है। इसके अंतर्गत, स्कूली और उच्च शिक्षा स्तर पर बदलाव किए जा रहे हैं ताकि शिक्षा प्रणाली रोजगारपरक बन सके।

6. वर्ल्ड-क्लास एजुकेशन और इंडस्ट्री एक्सपोजर

भारत में कई विश्वविद्यालय और कॉलेज अब वर्ल्ड-क्लास एजुकेशन और रिसर्च-ओरिएंटेड प्रोग्राम्स की ओर बढ़ रहे हैं। विदेशी विश्वविद्यालयों और कंपनियों के साथ सहयोग से भी छात्रों को इंडस्ट्री एक्सपोजर मिल सकता है।

निष्कर्ष

शिक्षा प्रणाली में समय के अनुसार बदलाव और जॉब मार्केट की मांगों के अनुसार शिक्षा प्रदान करना जरूरी है। इसके लिए सरकार, संस्थान, और इंडस्ट्री के बीच बेहतर सहयोग की जरूरत है। इससे न केवल रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, बल्कि छात्रों के लिए करियर में स्थिरता और संतोष भी सुनिश्चित हो सकेगा।

मौन की शक्ति

विजय गर्ग

आज के दौर में हर कोई भाग-दौड़ और प्रतिस्पर्धा में लिप्त है। हर तरफ शोर, सूचनाओं की बाढ़ और एक अंतहीन होड़ हमें घेर लेती है। सोशल मीडिया के शोर ने हमारे भीतर मानसिक और भावनात्मक कोने को लगभग खत्म कर दिया है। हम हर समय किसी न किसी तरह के शोर से घिरे होते हैं। ऐसे में मौन की शक्ति और उसकी प्रासंगिकता को समझना पहले से कहीं अधिक आवश्यक हो गया है। मौन सिर्फ शब्दों की अनुपस्थिति नहीं है, यह एक गहरा आत्म-संवाद है। यह वह स्थिति है, जहां हम बाहरी दुनिया से कटकर अपनी आंतरिक दुनिया से जुड़ते हैं। आधुनिक जीवन की आपाधापी में हम इस मौन की जरूरत को भूलते जा रहे हैं। एक श्लोक है- 'मौनं सर्वार्थसाधकम्', यानी मौन सभी कार्यों को सिद्ध करने वाला है। इसका तात्पर्य यह है कि मौन में अपार शक्ति छिपी होती है, जो हमें आत्मनिरीक्षण का अवसर देती है। हम जब मौन होते हैं, तब हमारे विचार स्पष्ट होते हैं और हम अपनी वास्तविक भावनाओं और उद्देश्यों को समझ पाते हैं। आज के समाज में जहां मानसिक स्वास्थ्य एक गंभीर चुनौती बन गया है, मौन और आत्मचिंतन के महत्त्व को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के अनुसार, हर पांच में से एक व्यक्ति अवसाद या मानसिक तनाव का सामना कर रहा है। ऐसे में मौन आत्मचिंतन का एक सशक्त साधन बन सकता है। जब हम मौन में होते हैं, तब हम अपने मन की गहराई तक पहुंचते हैं। यही वह स्थान है, जहां हम अपने दुख, तनाव, और चिंताओं से उबरने के रास्ते खोज सकते हैं।

मौन की इस प्रक्रिया में हमें खुद को जानने और अपने भीतर की आवाज को सुनने का अवसर मिलता है। मौन से जुड़े लोगों को समाज अक्सर गलत समझता है। लोग उन्हें उदास या अकेला मानते हैं। जबकि सच्चाई यह है कि मौन व्यक्ति गहरे आत्म-चिंतन में होता है। वह अपने विचारों और भावनाओं को समझ रहा होता है, जो शोर-शराबे में खो जाता है। मौन हमें खुद के साथ-साथ दूसरों के प्रति भी संवेदनशील बनाता है। जब हम मौन के माध्यम से अपने दुख और कष्टों को समझते हैं, तभी हम दूसरों की पीड़ा को भी गहराई से अनुभव कर पाते हैं। यही मौन हमें करुणामय बनाता है और समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी का अहसास कराता है। आधुनिक समाज में जहां हर कोई दूसरों से आगे निकलने की होड़ में है, मौन हमें यह सिखाता है कि असली सफलता बाहरी शोर में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति में है। सोशल मीडिया के इस युग में हर कोई अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहता है। ऐसे में मौन हमें यह सिखाता है कि खुद से जुड़े रहना कितना महत्त्वपूर्ण है। हमें यह समझना चाहिए कि हर समय खुद को प्रकट करने से बेहतर है कि हम कुछ पल मौन में बिताएं, खुद से जुड़ें और अपने जीवन की दिशा पर चिंतन करें। दार्शनिक प्लेटो कहा था, 'अज्ञानी होना कोई अपराध नहीं, लेकिन अज्ञानी बने रहना और सत्य की खोज न करना अपराध है।' यह मौन हमें सत्य की ओर ले जाने वाला सबसे सशक्त माध्यम है। मौन में हम अपने सवालों के जवाब ढूंढ़ते हैं, अपनी चुनौतियों का सामना करते हैं और अपनी ताकत को पहचानते हैं।

एक मशहूर उक्ति है- 'असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय', यानी हमें असत्य से सत्य की ओर और अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। मौन हमें इसी सत्य और प्रकाश की ओर ले जाता है। यह हमें खुद को समझने और दुनिया को एक नए दृष्टिकोण से देखने का अवसर देता है। आज की दुनिया में, जहां बाहरी दिखावा और शोर ने हमें अपने आप से दूर कर दिया है, मौन ही वह माध्यम है, जो हमें आत्मबोध की ओर ले जाता है। यह न केवल हमारे भीतर की शांति और स्थिरता का स्रोत है, बल्कि यह हमारे जीवन की जटिलताओं को समझने और उनसे निपटने की शक्ति भी देता है। आधुनिक समाज में ज्यादातर लोग खुद को प्रकट करने में लगे हैं, उसमें मौन हमें सिखाता है कि कभी-कभी खुद को न प्रकट करना, बल्कि खुद को सुनना ज्यादा महत्त्वपूर्ण होता है। मौन की यह यात्रा हमें खुद से जोड़ती है और हमें अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानने का अवसर देती है। जब हम मौन के साथ समय बिताते हैं, तो हमें अहसास होता है कि असली शक्ति और संतुलन बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। यह मौन हमें न केवल आत्मबोध की ओर ले जाता है, बल्कि हमें दूसरों के प्रति अधिक संवेदनशील और करुणामय भी बनाता है। आज की तेज-तर्रार जिंदगी में हर कोई दौड़ में शामिल है, मौन ही वह ठहराव है, जो हमें सही दिशा दिखाता है। यह एक ऐसी शक्ति है, जो हमें शांति के साथ संतुलित जीवन जीने का मार्ग सिखाती है। मौन हमें सिखाता है कि कभी-कभी सबसे गहरे उत्तर उस मौन में मिलते हैं, जिसे हम अक्सर अनसुना कर देते हैं। दुनिया चाहे कितनी ही शोर-शराबे से भरी हो, असली समाधान और सच्ची शांति हमें मौन की इस गहराई में ही मिलती है।

सेंसेक्स-निफ्टी में आ सकती थी और भी बड़ी गिरावट, कौन-सी ताकत बचा रही भारतीय शेयर बाजार को?

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। एक समय था, जब विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) के बाजार से जरा सा मुंह फेर लेने से सेंसेक्स हलकान हो जाता था और बाजार में त्राहि-त्राहि मच जाती थी। कोरोना महामारी के बाद मैन्युफैक्चरिंग की तरह बाजार भी धीरे-धीरे आत्मनिर्भर बनता जा रहा है। घरेलू संस्थागत निवेशकों का बाजार के प्रति रुझान लगातार बढ़ रहा है और उनके दम से बाजार की निर्भरता एफआईआई पर से कम हो रही है।

अक्टूबर में 1 लाख करोड़ से अधिक की बिकवाली

अक्टूबर माह में ही एफआईआई ने भारतीय बाजार से एक लाख करोड़ से अधिक निकाल लिए, लेकिन बाजार फिर भी उस प्रकार के औंधे मुंह नहीं गिरा, जैसा कि पहले गिरता था। क्योंकि गत अक्टूबर माह में घरेलू संस्थागत निवेशक (डीआईआई) ने घरेलू बाजार में अब तक का सबसे अधिक एक लाख करोड़ रुपए का मासिक निवेश किया।

स्टॉक एक्सचेंज के आंकड़ों के मुताबिक, इस साल अक्टूबर में एफआईआई ने 413,706 करोड़ की बिकवाली तो 299,260 करोड़ रुपए की खरीदारी की। मतलब खरीदारी के मुकाबले 1,14,445 करोड़ रुपए की अधिक बिकवाली की। दूसरी तरफ डीआईआई ने अक्टूबर माह में 340,159 करोड़ की खरीदारी तो 232,904 करोड़ की बिकवाकी की। मतलब घरेलू निवेशकों ने 107,254 करोड़ की शुद्ध खरीदारी की।

मौजूदा वित्त वर्ष में FII का बिकवाली पर जोर

चालू वित्त वर्ष 2024-25 में अप्रैल, मई, अगस्त और अक्टूबर में एफआईआई ने खरीदारी से अधिक बिकवाली की है, लेकिन डीआईआई पिछले साल जुलाई के बाद हर महीने बिकवाली से अधिक खरीदारी कर रहे हैं जो भारतीय निवेशकों को अपने बाजार में बढ़ते भरोसे को दर्शाता है।

इस साल अक्टूबर से पहले डीआईआई ने गत मार्च माह में सबसे अधिक 56,311 करोड़ की शुद्ध खरीदारी की थी। सोमवार को भी एफआईआई ने खरीदारी से 4329 करोड़ रुपए की अधिक बिकवाली की जबकि डीआईआई ने बिकवाली से 2936 करोड़ रुपए की अधिक खरीदारी की।

8 की जगह 15 फीसदी तक भी गिर सकता

लेमोन मार्केट डेस्क के रिसर्च एनालिस्ट गौरव गर्ग कहते हैं कि अक्टूबर माह में एक लाख करोड़ से अधिक के निवेश के बाहर जाने के बावजूद सेंसेक्स में अपने शीर्ष स्तर से आठ प्रतिशत की गिरावट रही, जबकि कुछ साल पहले का यह समय होता तो बाजार में 10-15 प्रतिशत की गिरावट होती। यह भारतीय निवेशकों की ताकत है जिसने बाजार को बचाकर रखा है।

इस साल सितंबर आखिर में सेंसेक्स 85,800 अंक के पार चला गया था। पिछले चार सालों में बाजार में कारोबार के जरूरी डीमैट खाते की संख्या तीन करोड़ से बढ़कर 18 करोड़ को पार कर गई है। जानकारों के मुताबिक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (एसआईपी) और म्युचुअल फंड को लेकर खुदरा निवेशकों के बीच लगातार बढ़ते रुझान से डीआईआई में बढ़ोतरी हो रही है।

ग्रामीण बैंकों की घटेगी संख्या, वित्त मंत्रालय ने उठाया बड़ा कदम

परिवहन विशेष न्यूज

सरकार देश में क्षेत्रीय बैंकों की संख्या कम करना चाहती है। देश में फिलहाल 43 ग्रामीण बैंक हैं। सरकार इस गिनती को घटाकर 28 तक लाना चाहती है। इसके लिए कुछ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में मर्जर करने का प्लान है। इससे बैंकों को लागत कम करने और कैपिटल बेस बढ़ाने में मदद मिलेगी। इन बैंकों की स्थापना आरआरबी अधिनियम 1976 के तहत की गई थी।

नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के विलय का चौथा चरण शुरू कर दिया है। इससे ऐसे बैंकों की संख्या वर्तमान के 43 से घटकर 28 हो जाएगी। इसके तहत विभिन्न राज्यों में 15 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विलय किया जाएगा।

आरआरबी का विलय आंध्र प्रदेश (जहां सबसे अधिक चार आरआरबी हैं), उत्तर प्रदेश तथा बंगाल (प्रत्येक में तीन) और बिहार, गुजरात, जम्मू-कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा तथा राजस्थान (प्रत्येक में दो) में किया जाएगा।

तेलंगाना के मामले में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विलय आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक (एपीजीवीबी) की परिसंपत्तियों व देनदारियों को एपीजीवीबी और तेलंगाना ग्रामीण बैंक के बीच विभाजित करने के अधीन होगा।

वित्तीय सेवा विभाग ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रमुखों को भेजे पत्र में कहा, 'एक राज्य-एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक' के लक्ष्य को हासिल करने के वास्ते क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को और अधिक समेकित करने की आवश्यकता महसूस की जा रही है।'

नाबार्ड के परामर्श से हो रहा काम

बयान में कहा गया है कि आगे के समेकन के लिए नाबार्ड के परामर्श से एक खाका तैयार किया गया है, जिससे आरआरबी की संख्या 43 से घटकर 28 हो जाएगी। वित्तीय सेवा विभाग ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के प्रायोजक बैंकों के प्रमुखों से 20 नवंबर तक टिप्पणियां मांगी हैं। तीन चरणों के विलय के माध्यम से 2020-21 तक ऐसे संस्थानों की संख्या 196 से घटकर 43 रह गई।

इन बैंकों की स्थापना आरआरबी अधिनियम, 1976 के तहत की गई थी, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे किसानों, कृषि मजदूरों व कारीगरों को ऋण तथा अन्य सुविधाएं प्रदान करना था। केंद्र की वर्तमान में आरआरबी में 50 प्रतिशत हिस्सेदारी है, जबकि 35 प्रतिशत तथा 15 प्रतिशत हिस्सेदारी क्रमशः संबंधित प्रायोजक बैंकों और राज्य सरकारों के पास है।

6.6 लाख करोड़ रुपये का डिपॉजिट

31 मार्च, 2024 तक के आंकड़ों के मुताबिक- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पास कुल 6.6 लाख करोड़ रुपये जमा थे। वहीं, उनका एडवांस 4.7 लाख करोड़ रुपये का था। प्रस्तावित मर्जर के बाद एक राज्य में एक ही क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक रह जाएगा।

अगर एसेट्स के हिसाब से देखें, तो देश में अब भी आधे से अधिक बैंकिंग सेक्टर पर सरकारी बैंकों की हिस्सेदारी है। सरकार ने बैंकों के कामकाज में सुधार करने और कैपिटल के लिए सरकार पर उनकी निर्भरता कम करने के लिए मर्जर करने की कोशिश की है।

महंगाई का लगेगा झटका! चाय, बिस्कुट और साबुन-तेल जैसी चीजों के बढ़ सकते हैं दाम

नई दिल्ली : हिंदुस्तान यूनिलीवर, गोदरेज, मैरिको और आईटीसी जैसी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स (FMCG) कंपनियां उपभोक्ताओं को महंगाई का झटका देने वाली हैं। दरअसल, खाद्य मुद्रास्फीति और उत्पादन लागत बढ़ने से साबुन, तेल, टूथपेस्ट और ग्रोसरी जैसे रोजमर्रा के सामान बनाने वाली FMCG कंपनियों का मार्जिन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। इसका असर कंपनियों के दूसरी तिमाही के वित्तीय नतीजों पर भी दिखा है।

FMCG कंपनियों की लागत क्यों बढ़ी?

FMCG कंपनियां पाम ऑयल, कॉफी और कोको जैसे प्रोडक्ट का इस्तेमाल कच्चे माल के तौर पर करती हैं। पिछले कुछ दिनों में इन चीजों के दाम में भारी उछाल आई है। इससे कंपनियों की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ गई है, जिसकी भरपाई के लिए कुछ कंपनियां दाम बढ़ाने पर विचार कर रही हैं।

हिंदुस्तान यूनिलीवर (HUL), गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड (GCPL), मैरिको, आईटीसी और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड (TCPL) ने शहरी खपत में कमी पर चिंता जताई है। एफएमसीजी सेक्टर की कुल बिक्री में शहरी खपत की हिस्सेदारी 65-68 प्रतिशत रहती है।

शहरों से ज्यादा गांवों में हो रही खपत

जीसीपीएल के एमडी और सीईओ सुधीर सीतापति ने दूसरी तिमाही के नतीजों की घोषणा पर कहा, 'हमें लगता है कि यह एक अल्पकालिक झटका है और हम विवेकपूर्ण मूल्य वृद्धि और लागत को स्थिर करके मार्जिन को ठीक कर लेंगे।' खास बात यह है कि ग्रामीण बाजार, जो पहले पीछे थे, ने शहरी बाजारों की तुलना में अपनी वृद्धि की रफ्तार को कायम रखा है। एक अन्य एफएमसीजी कंपनी डाबर इंडिया ने भी कहा कि सितंबर तिमाही में मांग का माहौल चुनौतीपूर्ण था, जिसमें 'उच्च खाद्य मुद्रास्फीति और शहरी मांग में कमी' शामिल थी।

सिंगापुर का पासपोर्ट सबसे मजबूत, पाकिस्तान का सबसे कमजोर; जानिए भारत की रैंकिंग

परिवहन विशेष न्यूज

एशियाई देश पिछले कई साल से हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में शीर्ष पर हैं। जापान सिंगापुर और दक्षिण कोरिया जैसे देश अक्सर दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट में टॉप पर रहते हैं। इससे पता चलता है कि इन देशों की वैश्विक स्तर पर बड़ी हैसियत है और इन्होंने कूटनीतिक संबंधों पर काफी बेहतर तरीके से काम किया है। आइए जानते हैं अन्य देशों के साथ भारत और पाकिस्तान की रैंकिंग।

नई दिल्ली। किसी भी देश के वैश्विक स्तर पर दबदबे का अंदाजा उसके पावरफुल पासपोर्ट से लगाया जा सकता है। मजबूत पासपोर्ट का पैमाना यह है कि कितने देश उसे वीजा-फ्री एंट्री देते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स ने दुनिया के 199 पासपोर्ट की रैंकिंग बनाई है कि कौन कितना मजबूत है। आइए दुनिया के टॉप 5 पावरफुल पासपोर्ट के बारे में जानते हैं। साथ ही, यह भी देखते हैं कि 199 पासपोर्ट की लिस्ट में भारत कौन-से नंबर पर है।

पासपोर्ट की रैंकिंग कैसे की जाती है?

हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में पासपोर्ट की रैंकिंग एक व्यापक पद्धति पर आधारित है। इसमें कई चीजों को पैमाना बनाया गया है, लेकिन ज्यादा जोर इस बात पर है कि पासपोर्ट धारक को कितने देश में वीजा फ्री एंट्री मिलती है। कोई पासपोर्ट अममून देश के राजनयिक संबंध और उसके अंतरराष्ट्रीय समझौते की बदौलत मजबूत बनता है।

सिंगापुर का कोई जवाब नहीं

हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के मुताबिक, साल 2024 में सबसे मजबूत सिंगापुर का पासपोर्ट है। अगर आप सिंगापुर के पासपोर्टधारक हैं, तो आपको 195 मुल्कों में घूमने-फिरने के लिए वीजा की जरूरत नहीं पड़ेगी।

ये पांच देश हैं दूसरे नंबर पर

पावरफुल पासपोर्ट की रैंकिंग में दूसरे पायदान पर पांच देश काबिज हैं- फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और स्पेन। इन देशों के नागरिक 192 पर्यटन स्थलों पर बिना वीजा के जा सकते हैं।

छोटे देशों की बड़ी हैसियत

हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की रैंकिंग में तीसरे नंबर पर सात देश हैं। इनमें ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फिनलैंड, आयरलैंड, लक्जमबर्ग, नीदरलैंड, दक्षिण कोरिया और स्वीडन शामिल हैं। अगर आपके पास इन देशों का पासपोर्ट है, तो आपको 191 देशों में वीजा-फ्री एंट्री मिलेगी।

इन देशों का भी दबदबा

बेल्जियम, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड और ब्रिटेन दुनिया के सबसे ताकतवर पासपोर्ट की लिस्ट में चौथे पायदान पर हैं। इन देशों के पासपोर्ट के साथ 190 डेस्टिनेशन पर जाने के लिए वीजा की दरकार नहीं रहेगी।

ऑस्ट्रेलिया-पुर्तगाल दमदार

हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में पांचवें नंबर ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल के पासपोर्ट हैं। इन देशों के पासपोर्ट धारक बिना वीजा के 189 मुल्कों में जा सकते हैं।

भारत का पासपोर्ट कितना पावरफुल?

भारत सबसे पावरफुल पासपोर्ट की रैंकिंग में 83वें स्थान पर है। मॉरिटानिया, सेनेगल और ताजिकिस्तान भी इसी नंबर पर हैं। भारतीय पासपोर्ट धारक 58 देशों में वीजा-फ्री एंट्री कर सकते हैं।

पाकिस्तान दुनिया के सबसे कमजोर पासपोर्ट में

रैंकिंग के अनुसार, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सीरिया, इराक, यमन और सोमालिया दुनिया में सबसे कम पावरफुल पासपोर्ट हैं। इन्हें बेहद सीमित देशों में वीजा फ्री एंट्री मिलती है।

RBI का 2000 के नोट पर बड़ा अपडेट, बंद होने के बाद भी हजारों करोड़ दबाकर बैठे हैं लोग

आरबीआई का कहना है कि 2000 रुपये के 98.04 प्रतिशत बैंक नोट बैंकिंग सिस्टम में वापस आ गए हैं। अब सिर्फ 6970 करोड़ रुपये के नोट जनता के पास हैं। आरबीआई ने पिछले साल मई में 2000 रुपये के बैंक नोट को चलन से वापस लेने का एलान किया था। उस वक्त कुल 3.56 लाख करोड़ रुपये मूल्य के 2000 रुपये के बैंक नोट चलन में थे।

नई दिल्ली। रिजर्व बैंक (RBI) ने करीब डेढ़ साल पहले 2000 रुपये के नोटों (2000 Rupee Note) को चलन से बाहर किया था। केंद्रीय बैंक ने लोगों को बाकायदा मोहलत भी दी कि वे इन नोटों को वापस बैंक को लौटा सकें। अब तक 2000 के करीब 98 फीसदी नोट आरबीआई के पास आ भी चुके हैं। लेकिन, अभी भी हजारों करोड़ के गुलाबी नोटों को लोग दबाए बैठे हैं।

लोगों के पास 6,970 करोड़ रुपये मूल्य के नोट

आरबीआई ने 2000 के नोट पर बड़ा अपडेट दिया है। उसका कहना है कि सर्कुलेशन से बाहर होने के बाद से ज्यादातर 2000 के नोट वापस आ गए हैं। लेकिन, अभी भी लोगों के पास 6,970 करोड़ रुपये मूल्य के नोट मौजूद हैं। यह आंकड़ा 31 अक्टूबर 2024 तक का है। आरबीआई का लेटेस्ट अपडेट बताता है कि 98.04 फीसदी 2000 रुपये के नोटों की वापसी हो चुकी है।

हालांकि, अब समस्या यह है कि केंद्रीय बैंक के पास नोट वापस आने की रफ्तार काफी सुस्त हो गई है। इसका मतलब यह भी हो सकता है कि जिनके पास ये नोट हैं, वे इसे लौटाना नहीं चाहते। पिछले एक महीने में महज 147 करोड़ रुपये मूल्य के गुलाबी नोट ही वापस आ सके हैं।

सुस्त पड़ रही नोट वापसी की रफ्तार

आरबीआई ने 1 जुलाई 2024 को जो डेटा शेयर किया था, उसके मुताबिक 7581 करोड़ रुपये के 2000 रुपये के नोट बाजार में बचे हुए थे। 1 अक्टूबर को ये 7,117 करोड़ रुपये और अब 31 अक्टूबर को 6,970 करोड़ रुपये है। इसका मतलब कि जुलाई से अब तक महज 611 करोड़ रुपये मूल्य के नोटों की वापसी हो सकी है।

पिछले साल मई 2023 में 2000 रुपये के नोट को चलन से बाहर किया गया था। उस वक्त बाजार में 3.56 लाख करोड़ रुपये मूल्य के करेंसी नोट मौजूद थे। 29 दिसंबर 2023 तक ये आंकड़ा घटकर 9,330 करोड़ रुपये रह गया, क्योंकि लोगों ने युद्ध स्तर पर 2000 के नोट जमा कराए। लेकिन, उसके बाद वापसी की रफ्तार लगातार धीमी होती गई।

2000 के नोट को चलन से बाहर क्यों किया गया था?

RBI ने क्लीन नोट पॉलिसी (Clean Note Policy) के तहत 19 मई 2023 को 2000 रुपये के नोट को वापस लेने की घोषणा की थी। केंद्रीय बैंक ने 2000 के नोट को बदलवाने के लिए पहले 30 सितंबर 2023 तक की मोहलत दी थी। हालांकि, इसे समय-समय पर बढ़ाया भी गया। 2000 के नोट नवंबर 2016 में पेश किए गए थे। उस वक्त सरकार ने चलन में मौजूद 500 और 1000 रुपये के नोटों बंद कर दिया था।

आरबीआई ने कहा कि 2018-19 में 2000 रुपये के बैंक नोटों की छपाई बंद करने का एलान किया। उसका कहना था कि अन्य मूल्य के नोटों की पर्याप्त उपलब्धता होने के बाद अब 2000 के नोटों की जरूरत नहीं रह गई।

किसकी जीत से भारतीय शेयर बाजार और अर्थव्यवस्था को होगा फायदा?

परिवहन विशेष न्यूज

US Elections 2024 भारत और अमेरिका के बीच काफी पुराने व्यापारिक संबंध हैं। अमेरिका लंबे समय से भारत का सबसे प्रमुख ट्रेड पार्टनर है। भारत की कई बड़ी आईटी फार्मा और एग्रो-केमिकल कंपनियों के लिए अमेरिका सबसे बड़ा बाजार है। यही वजह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव पर भारत की करीबी नजर है। आइए जानते हैं कि ट्रंप और हैरिस में से किसकी नीतियां भारत के लिए फायदेमंद होंगी।...

नई दिल्ली। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में कमला हैरिस (Kamala Harris) और डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। दोनों ही नेताओं की नीतियों में जमीन-आसमान का फर्क है। खासकर, व्यापार, रक्षा और फार्मा सेक्टर की नीतियों में। इनका सीधा भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। साथ ही, दोनों नेताओं का प्रवासियों को लेकर नजरिया भी काफी अलग है।

आइए जानते हैं कि भारत को लेकर हैरिस और ट्रंप की आर्थिक नीतियों में क्या फर्क है और किसके जीतने की सूरत में भारतीय शेयर बाजार और अर्थव्यवस्था को अधिक फायदा होगा।

शेयर मार्केट पर कैसा होगा असर?

अमेरिका जाहिर तौर पर भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक सहयोगी है। भारत की आईटी, फार्मा, कंपनियों के लिए अमेरिका सबसे बड़ा बाजार है। ऐसे में अमेरिकी नीतियों का भारतीय बाजार पर असर पड़ना लाजिमी है। यही वजह है कि भारतीय निवेशक चुनावी नतीजों से पहले काफी सतर्क रुख अपना रहे हैं।

अगर ऐतिहासिक रूप से देखें, तो डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के मुकाबले कमला हैरिस की डेमोक्रैटिक पार्टी का सत्ता में रहना भारतीय शेयर बाजार के लिए अधिक फायदेमंद रहा है। 2005 से अब तक के आंकड़े देखें, तो निफ्टी ने डेमोक्रैटिक पार्टी के राष्ट्रपतियों के कार्यकाल में ज्यादा बेहतर रिटर्न दिया है।

प्रवासियों को लेकर नजरिया

सत्तारूढ़ डेमोक्रैटिक पार्टी (Democratic Party) की उम्मीदवार कमला हैरिस का प्रवासियों को लेकर काफी संतुलित नजरिया है। वह बिना दस्तावेज वाले शरणार्थियों, खासकर बच्चों को अमेरिकी नागरिकता देने की वकालत करती हैं। कुशल श्रमिक वीजा जैसे कि H-1B का विस्तार के भी हक में हैं। वहीं, ट्रंप सख्त सीमा नियंत्रण के पक्षधर हैं।

राष्ट्रपति	पार्टी	कार्यकाल	निफ्टी रिटर्न
जो बाइडेन	डेमोक्रैटिक पार्टी	2021 से अब तक	75 फीसदी
डोनाल्ड ट्रंप	रिपब्लिकन पार्टी	2017-2021	38 फीसदी
बराक ओबामा (Term II)	डेमोक्रैटिक पार्टी	2013-2017	117 फीसदी
बराक ओबामा (Term I)	डेमोक्रैटिक पार्टी	2009-2013	45 फीसदी
जॉर्ज बुश	रिपब्लिकन पार्टी	2005-2009	45 फीसदी

इस मामले में कमला हैरिस का रुख भारतीयों के लिए ज्यादा फायदेमंद है। प्रवासियों को लेकर उदार नजरिए अमेरिका में रहने वाले भारतीय परिवारों को स्थिरता और सुरक्षा का माहौल मिल सकता है। वहीं, ट्रंप की सख्त नीतियां अकुशल श्रमिकों पर बुरा असर डाल सकती हैं। लेकिन, आईटी सर्विसेज पर इसका प्रभाव पड़ने की आशंका नहीं है, जो भारत के लिए अच्छी बात है।

व्यापार नीति में भी बड़ा फर्क

व्यापार नीति के मामले में भी कमला हैरिस का नजरिया उदारवादी है। वह बहु-पक्षीय व्यापार समझौतों और क्षेत्रीय सहयोग (जैसे, इंडो-पैसिफिक आर्थिक ढांचा) पर जोर देती हैं। लेकिन, ट्रंप की नीति घरेलू उद्योग को बढ़ावा देने का है। वह विदेशी आयात पर भारी शुल्क लगाने के पक्षधर हैं। उनकी अगुआई में अमेरिका की चीन से ट्रेड वॉर शुरू हुई थी।

इस लिहाज से अगर कमला हैरिस जीतती हैं, तो भारत और अमेरिका के मौजूदा व्यापारिक संबंधों को कोई बड़ा बदलाव होने की संभावना नहीं है। लेकिन, ट्रंप की नीतियां वैश्विक व्यापार में उथल-पुथल मचा सकती हैं, जो पहले ही अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है। हालांकि, इससे भारतीय कंपनियों के सामने यह भी मौका रहेगा कि वह अमेरिका में चीनी कंपनियों की जगह हथिया सकें।

"वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर पत्थरबाज़ी की बढ़ती घटनाएं चिंताजनक"

पत्थरबाज़ी की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए रेलवे पुलिस को सख्त कदम उठाने चाहिए : संजीव कुमार सिंह एड्वोकेट

देश की संपत्ति की सुरक्षा केवल सरकार की ही नहीं बल्कि हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी और संवैधानिक कर्तव्य : एड्वोकेट कृष्ण मुरारी माहेश्वरी

ऐसी घटनाएं न केवल सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाती हैं, बल्कि यात्रियों की सुरक्षा पर भी खतरा डालती हैं : समाजसेवी पंकज जैन

रेलवे देश की अमूल्य संपत्ति है और इसकी सुरक्षा सभी नागरिकों की जिम्मेदारी : वरिष्ठ समाजसेवी चंद्रवीर सिंह फ़ौजदार

आगरा,संजय साग़र सिंह। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर यूपी में पत्थरबाजी का सिलसिला रुक नहीं रहा है। रविवार को गाड़ी संख्या 22436 वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस पर बुलन्द शहर जिला के कमालपुर - डाबर के बीच कोच C3 बर्थ 53/54 पर असमाजिक तत्वों के द्वारा पत्थरबाज़ी कर ट्रेन को क्षति पहुँचायी गयी।

संजीव कुमार सिंह एड्वोकेट ने वंदे भारत ट्रेन पर पथराव की घटनाओं की गंभीरता को लेकर रेलवे पुलिस और प्रशासन से सख्त कदम उठाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि वंदे भारत ट्रेन में पत्थरबाजी की 1503 घटनाएं से मैं हतप्रभ और स्तब्ध हूँ। इन घटनाओं से न केवल सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंची हैं, बल्कि यात्रियों की सुरक्षा पर भी सवाल खड़ा हुआ है। ऐसी घटनाएं निंदनीय हैं और किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं की जा सकतीं है। ऐसी घटनाएं न केवल सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाती हैं, बल्कि यात्रियों की सुरक्षा पर भी खतरा डालती हैं। समाज में इस तरह की हरकतें न केवल असुरक्षा की भावना पैदा करती हैं, बल्कि हमारे देश की छवि को भी नुकसान पहुंचाती हैं। इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए केंद्रीय रेल मंत्री, रेलवे पुलिस और प्रशासन को सख्त कदम उठाने चाहिए, साथ ही समाज में जागरूकता भी फैलानी चाहिए।

देश की संपत्ति की सुरक्षा केवल सरकार की ही नहीं बल्कि हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी और संवैधानिक कर्तव्य : एड्वोकेट कृष्ण मुरारी माहेश्वरी

एड्वोकेट कृष्ण मुरारी माहेश्वरी ने रेल मंत्री, रेलवे पुलिस और प्रशासन से इस पर सख्त कार्वाई करने और ऐसी घटनाओं के प्रति समाज को जागरूक करने का आग्रह किया। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए अभिभावकों और स्कूल शिक्षकों से बच्चों को इस विषय पर जागरूक करने का भी आह्वान किया। उन्होंने अभिभावकों और अध्यापकों का आह्वान करते हुए कहा कि परिवार में माता-पिता और स्कूलों में अध्यापकों द्वारा बच्चों को इस विषय पर जागरूक करना आवश्यक है जिससे न केवल ऐसी घटनाएं कम होंगी, बल्कि रेलवे यात्रियों की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो पाएगी। हम सभी को एक जागरूक नागरिक बनना चाहिए। यह देश हमारा है, और देश की संपत्ति की सुरक्षा केवल सरकार की ही नहीं बल्कि हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी और संवैधानिक मूल कर्तव्य है।

ऐसी घटनाएं न केवल सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाती हैं, बल्कि यात्रियों की सुरक्षा पर भी खतरा डालती हैं : समाजसेवी पंकज जैन

समाजसेवी पंकज जैन ने इस बात पर जोर दिया कि समाज में जागरूकता फैलाना आवश्यक है, खासकर अभिभावकों और शिक्षकों के माध्यम से, ताकि बच्चों को इस विषय पर समझाया जा सके। उनका कहना था कि ऐसी घटनाएं न केवल सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाती हैं, बल्कि यात्रियों की सुरक्षा पर भी खतरा डालती हैं। उन्होंने कहा, रेलवे देश की अमूल्य संपत्ति है और इसकी सुरक्षा सभी नागरिकों की जिम्मेदारी है। इस तरह की घटनाएं देश की छवि को नुकसान पहुंचाती हैं और इसके लिए सख्त उपाय करने की आवश्यकता है। उन्हें यह भी चिंता है कि पथराव की घटनाएं बढ़कर 1503 तक पहुंच गईं, जिससे रेलवे को करोड़ों का नुकसान हुआ। श्री जैन ने सभी से अपील की कि वे जागरूक नागरिक बनें और रेलवे की सुरक्षा को सुनिश्चित करने में योगदान दें।

रेलवे देश की अमूल्य संपत्ति है और इसकी सुरक्षा सभी नागरिकों की जिम्मेदारी : वरिष्ठ समाजसेवी चंद्रवीर सिंह फ़ौजदार

वरिष्ठ समाजसेवी चंद्रवीर सिंह फ़ौजदार ने कहा, रविवार को वंदे भारत ट्रेन पर बुलंदशहर जिले के कमालपुर स्टेशन को पार किया, तभी बाहर से किसी असामाजिक तत्व ने पत्थर फेंके, जिससे ट्रेन के शीशे चकनाचूर हो गये। एक रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2022 में ऐसी घटनाओं का आंकड़ा 1503 तक पहुंच गया, जिससे रेलवे को करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ। यह आंकड़ा सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर इस तरह की घटनाएं बार-बार क्यों हो रही हैं ? ट्रेन पर पथराव से न केवल संपत्ति को क्षति होती है, बल्कि यह यात्रियों के लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है। वहीं, यह समझने की आवश्यकता है कि रेलवे देश की एक अमूल्य संपत्ति है और इसका संरक्षण देश के हम सभी नागरिकों की जिम्मेदारी है।

झारखंड सी एम के विधायक प्रतिनिधि समेत तीन राज्यों में चुनाव पूर्व छापे

50 लाख रुपये, एक किलो सोना बरामद

कुमार परिच्छा, स्टेट हेड

रांची। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग से ठीट 8 दिन पहले सी बी आई एवं अन्य एजेंसियों ने मंगलवार सुबह करीब 11 बजे बड़ी कार्रवाई की है। 1200 करोड़ रुपए के अवैध खनन मामले में झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार में 16 ठिकानों पर छापेमारी जारी है। जहां 50 नगद लाख कैस एवं एक किलो सोना, चांदी समेत करोड़ों रूपये के दस्तावेज जप्त हुए हैं।

जानकारी के अनुसार झारखंड के साहिबगंज के11 जगहों पर छापेमारी हुई तो रांची में 3 और कोलकाता और पटना में एक-एक जगह पर रेड किया गया। सीबाआई ने राजमहल उधवा के बड़े कारोबारी महताब आलम, मिर्जाचौकी के रंजन वर्मा, संजय जायसवाल, बरहरवा के सुब्रतो पाल, पत्थर व्यवसायी टिंकल भगत, अवध किशोर सिंह उर्फ पतरु सिंह, बरहरवा के भगवान भगत और कृष्णा शाह के यहां छापेमारी की। ये सभी लोग पंकज मिश्रा के करीबी माने जाते हैं।

पंकज मिश्रा बरहट विधानसभा के विधायक हेमंत सोरेन के प्रतिनिधि हैं। पंकज मिश्रा और कई लोगो के खिलाफ अवैध खनन मामले सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की थी।यह प्राथमिकी 2023 में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की थी। नवंबर 2023 में झारखंड हाई कोर्ट ने सीबीआई को आदेश दिया कि वह साहिबगंज के निम्बू पहाड़ में पत्थर की अवैध चोरी और खनन के मामले में जांच करे। कोर्ट ने यह भी नोट किया कि मूल डब्ल्यूपी दायर करने वाला याचिकाकर्ता इसे वापस लेना चाहता था। हाई कोर्ट ने सीबीआई से याचिकाकर्ता द्वारा बाद में दायर वकालतनामें की वास्तविकता की जांच करने को कहा। इसमें दो व्यक्तियों की भूमिका - अशोक यादव और मुकेश यादव की सामने आई। जिन्होंने याचिकाकर्ता को उच्च न्यायालय के परिसर में उस समय धमकाया जब वह याचिका का प्रतिनिधित्व करने के लिए एनओसी प्राप्त कर रहा था। इस मामले में पंकज मिश्रा समेत सात आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। ईडी ने झारखंड में अवैध कोयला खनन मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पंकज मिश्रा को गिरफ्तार किया था। सुप्रीम कोर्ट ने पंकज मिश्रा को जमानत दे दी थी।

यही राष्ट्रवाद के उदय का सम्मान.....

स्वतंत्र लेखक - हरिहर सिंह चौहान इन्दौर

"भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ।" यही भाव हम सभी का होना चाहिए। राष्ट्रवाद के हिलोरे ले रहे इस सफरनामा में कुछ ऐसे वाक़िए, घटना, अनहोनी कहें या फिर हमारा अपने देश के प्रति समर्पण के भाव का दृष्टिकोण, जिसमें राष्ट्र ही सर्वोपरि रहा हो, तो ऐसे संकेत या अनोखी सजा जबलपुर उच्च न्यायालय ने इस बात को ध्यान में रखते हुए जब २१ बार तिरंगे को सलाम और भारत माता की जय बोलने की दी तो मन प्रफुल्लित हो गया। हाल ही में रील बनाने के चक्कर में कुछ दोस्तों ने मिलकर खुरापाती चक्रव्यूह रचा और इस वीडियो में पकिस्तान के समर्थन में नारे लगाते हुए इसे इन्टरनेट पर बहुप्रसारित कर दिया। तब पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी फैजान को जेल भेज दिया। फैजान ने जमानत की गुहार लगाई तो न्यायालय ने उसे पश्चाताप का मौका देते हुए विशिष्ट शर्त पर जमानत दे दी। इसमें प्रत्येक माह के प्रथम और चौथे मंगलवार को भोपाल के थाने में सुबह तिरंगे को २१ बार सलामी देगा और २१ बार ही भारत माता की जय बोलेगा। युवा पीढ़ी ज़रा-से प्रचार के चक्कर में भटक जाती है। इन्हीं भटके हुए नवजवानों को देश के प्रति समर्पित करने का वक्त आ गया है। जिस प्रकार सम्मान-मान- मर्यादा होना अच्छे इंसान का फ़र्ज़ है, उसी प्रकार अपने देश के प्रति समर्पित होना ही होगा। इस तरह की सकारात्मक पहल से युवा पीढ़ी में राष्ट्रवाद के उदय का सही समय है। नौजवानों ने गुलाम भारत की वह पीडा नहीं झेली है, वह लाठी, गोली, बन्दूक व अन्य यातनाएं नहीं सही हैं, इसलिए उन्हें देश के प्रति समर्पण भाव नहीं आते हैं।

भारत एक देश मात्र नहीं है, भारत भविष्य का आइना है। यह 'वसुधैव कुटुम्बकम के भाव के साथ एकता व अखंडता का सही साथी है। भारत सत्य-अहिंसा का प्रबल पक्षकार है। देश-दुनिया में सबसे मिलनसार एवं विश्व शांति का हितैषी भारत है तथा युवाओं को इस बात का बोध कराना हम सभी की सामाजिक व राष्ट्रीय जिम्मेदारी है। नव वर्ष, ईद, होली, दीपावली मानने और मनाने वाले भारत में सभी धर्म-जातियों का गठजोड़ है। यही एकता हमें कुटुम्ब बनाती है। भाईचारे को बढ़ाती है, भेदभाव को मिटाने के लिए यह सबसे पहले काम आती है, क्योंकि दशकों से गंगा-जमुनी संस्कृति, एकता-भाईचारे का साथ रहा, पर कुछ वर्षों से आधुनिकता की अंधी दौड़ चल रही है, जिसमें हम अपने आज को कहीं खो ना बैठें। यह अंतराल जो कल-आज-कल में आ गया है, उसके कारण युवा पीढ़ी भटकाव के रास्ते पर चल पड़ी है। इन्हें सुधारने हेतु एक ही बात कहना होगी कि "है प्रीत जहां की रीत, मैं बात वहां की सुनाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात बताता हूँ।"

हमारे पड़ोसी दुश्मन देश इस भाईचारे को तुड़वाने के लिए धर्म- जात-पात के नाम पर आपस में वैमनस्य पैदा करना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसी मजबूत संस्था व व्यक्ति हैं, जो इस पर सख्त कार्रवाई करते हैं। जनसेवा- राष्ट्रसेवा के भाव से ओत-प्रोत भारत की न्यायपालिका जब मजबूत है। कानून की पकड़ से कोई भी मुल्ज़िम नहीं बच सकता है, पर युवा वर्ग अगर कुछ देशद्रोही काम करता है तो उसके विचारों के भटके भविष्य कों सुधारने हेतु एक मौका देकर उस युवा विचार को देश से जोड़ने हेतु न्यायालय अनूठी सजा देता है। ऐसी न्यायपालिका को साधुवाद। राष्ट्र के प्रति जिम्मेदार होने का फ़र्ज़ हम सभी को मिलकर निभाना होगा। ऐसे ही यह गुलशन हमेशा आबाद रहेगा और इसी से युवा पीढ़ी में राष्ट्रवाद का उदय होगा, क्योंकि हम सभी के लिए भारत सर्वप्रथम होना चाहिए। यही राष्ट्रवाद का सम्मान भी है।

नंदनकानन एक्सप्रेस पर गोलीबारी की गई

मनोरंजन सासमल, स्टेट हेड ओड़िशा

भुबनेश्वर: नंदनकानन एक्सप्रेस पर गोलीबारी की गई। फायरिंग में केबिन की खिड़की का शीशा टूट गया। 2 राउंड फायरिंग की गई। शूटिंग भद्रक और बौडपुर स्टेशनों के बीच हुई। जांच शुरू कर दी गई है। बदमाशों को पकड़ने और उनके मकसद का पता लगाने के प्रयास शुरू कर दिए गए हैं।न्यू दिल्ली से भुबनेश्वर जाता है।

लोक गायिका शारदा सिन्हा का निधन

बिहार कोकिला शारदा सिन्हा का निधन हो गया। उन्होंने दिल्ली के एम्स में अंतिम सांस ली। उनका 11 दिनों से एम्स में इलाज चल रहा था। वो पिछले छह वर्षों से ब्लड कैंसर से जूझ रही थीं। शारदा सिन्हा मैथिली और भोजपुरी की एक प्रसिद्ध लोक गायिका थी जिन्हें बिहार कोकिला के नाम से भी जाना जाता था।

नई दिल्ली। अपनी मधुर आवाज के लिए 'बिहार कोकिला' के नाम से प्रसिद्ध पद्म भूषण से सम्मानित शारदा सिन्हा (Sharda Sinha) का आज निधन हो गया। उन्होंने दिल्ली के एम्स में अंतिम सांस ली। एम्स ने शारदा सिन्हा के निधन की पुष्टि की है। वह 11 दिनों से एम्स में भर्ती थीं। वह पिछले छह वर्षों से ब्लड कैंसर से जूझ रही थीं। पिछले दिनों उनकी तबीयत बिगड़ने पर 26 अक्टूबर को एम्स में भर्ती किया गया था। शारदा सिन्हा को सोमवार रात से दिल्ली के एम्स में वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया था। उनके बेटे अंशुमान सिन्हा ने दोपहर को ही इस बारे में जानकारी दी थी।

पीएम मोदी ने जताया शोक

पीएम मोदी ने सोशल साइट एक्स पर पोस्ट कर कहा, सुप्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा जी के निधन से अत्यंत दुख हुआ है। उनके गाए मैथिली और भोजपुरी के लोकगीत पिछले कई दशकों से बेहद लोकप्रिय रहे हैं। आस्था के महापर्व छठ से जुड़े उनके सुमधुर गीतों की गूंज भी सदैव बनी रहेगी। उनका जाना संगीत जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति है। शोक की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिजनों और प्रशंसकों के साथ हैं। ओम शांति !

बिहार सीएम ने भी जताया शोक

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी लोक गायिका के निधन पर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि बिहार कोकिला शारदा सिन्हा ने मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका के अलावा हिंदी गीत भी गाए थे। उन्होंने कई हिंदी फिल्मों में भी आवाज दी है। उनके निधन से संगीत के क्षेत्र में अपूरणीय क्षति हुई है।

दिल्ली सीएम ने जताया शोक

दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, प्रसिद्ध लोकगायिका शारदा सिन्हा जी के निधन की खबर बहुत दुखद है। उन्होंने अपने संगीत से हमारी सांस्कृतिक धरोहर को संजोने का काम किया। ईश्वर उन्हें अपने श्रीचरणों में स्थान दें।

मंत्री कृष्ण पात्र के मुँह पर सिंघम डायलॉग

मनोरंजन सासमल, स्टेट हेड ओड़िशा

भुबनेश्वर: मंत्री के मुँह पर सिंघम डायलॉग। आपूर्ति सहायकों की बैठक में खाद्य मंत्री ने सिंघम फिल्म का डायलॉग सुनाकर दी सलाह। उन्होंने कहा, सिंघम फिल्म में एक डायलॉग है, अगर पुलिस आपको मंदिर ले जाना चाहेगी तो जूता नहीं चुराएगा। इसी प्रकार यदि आप बाजार खराब नहीं करना चाहते तो नही होगा।इसके साथ ही महाभारत में भीष्म शरशैया की कहानी बताई गई और चेतावनी दी गई। उन्होंने कहा, जब भीष्म सो रहे थे, तो कृष्ण ने उनसे कहा कि हालांकि उन्होंने कुछ नहीं किया है, लेकिन द्रौपदी को उनके वस्त्र छीनते देखने के लिए उन्हें दंडित किया जा रहा है। इसलिए मंत्री ने अन्याय या भ्रष्टाचार करने वालों और अन्याय को बढ़ावा देकर चुपचाप रहने वालों पर कार्रवाई करने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि बीजेडी सरकार के दौरान बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ था लेकिन मैंने इस विभाग को पारदर्शी बनाने की शपथ ली है। इसलिए मंत्री ने सहायकों को धान खरीदते समय पारदर्शिता बरतने की सलाह दी।

पानी में घुलनशील उर्वरक: पर्यावरण के अनुकूल और फ़सल उत्पादकता में सुधार की कुंजी

जल-घुलनशील उर्वरकों जैसे पर्यावरण के अनुकूल और कुशल उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा देने वाली नीतियों और सब्सिडी को मज़बूत किया जाना चाहिए। जल-घुलनशील उर्वरकों को अन्य टिकाऊ कृषि पद्धतियों, जैसे फ़सल चक्रण, कार्बनिक पदार्थ समावेशन और जल प्रबंधन तकनीकों के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए। जल-घुलनशील उर्वरक मक्का चारा उत्पादन में पारंपरिक उर्वरकों के लिए एक टिकाऊ और कुशल विकल्प का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे उर्वरक उपयोग दक्षता में सुधार करते हैं, मिट्टी के स्वास्थ्य को बहाल करते हैं और गुणवत्ता से समझौता किए बिना उच्च चारा उपज सुनिश्चित करते हैं। जल-घुलनशील उर्वरक एक संतुलित, पर्यावरण के अनुकूल और लागत प्रभावी दृष्टिकोण प्रदान करते हैं जो पर्यावरणीय जोखिमों को कम करते हुए किसानों को कृषि उत्पादकता बनाए रखने में मदद कर सकते हैं।

-डॉ.सत्यवान सौरभ

पानी में घुलनशील उर्वरक-उर्वरक का उपयोग दक्षता बढ़ाने, मिट्टी के स्वास्थ्य को बहाल करने और मक्का जैसी चारा फसलों में उच्च पैदावार को बनाए रखने के लिए एक प्रमुख कृषि-अवरोध के रूप में उभरा है। पारंपरिक उर्वरक अक्सर असमान पोषक तत्व वितरण, खराब फ़सल प्रतिक्रिया और पर्यावरणीय नुक़सान का कारण बनते हैं। इसके विपरीत, पानी में घुलनशील उर्वरक एक संतुलित पोषक आपूर्ति प्रदान करते हैं, मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करते हैं और फोरेज में नाइट्रेट संचय जैसे मुद्दों को रोकते हैं, जो पशुधन को नुक़सान पहुँचा सकते हैं।

चारा उत्पादन में उर्वरक आवेदन महत्त्वपूर्ण है, लेकिन यह चुनौतियों के साथ आता है। मक्का के चारे में बायोमास और कच्चे प्रोटीन को बढ़ाते हुए, नाइट्रोजन-भारी उर्वरकों के परिणामस्वरूप नाइट्रेट संचय हो सकता है, जो पशुधन को नुक़सान पहुँचा सकता है। प्रभावी उर्वरक उपयोग संतुलित पोषक तत्वों की आपूर्ति, फ़सल प्रतिक्रिया में सुधार और पर्यावरणीय प्रभावों को कम करता है। अंधाधुंध उर्वरक आवेदन के कारण फ़सल की पैदावार खराब हो सकती है, मिट्टी के स्वास्थ्य का क्षरण और प्रदूषण हो सकता है।

क्षेत्र परीक्षण पोषक तत्वों की आपूर्ति, पोषक तत्वों का उपयोग दक्षता और फ़सल प्रतिक्रियाओं में पर्याप्त परिवर्तनशीलता को प्रकट करते हैं। क्षेत्रों में इस तरह की विसंगतियाँ समग्र चारा उत्पादकता को प्रभावित करती हैं। इन अक्षमताओं का मुकाबला करने के लिए, विशिष्ट क्षेत्र विशेषताओं के अनुरूप सटीक पोषक तत्व और फ़सल प्रबंधन आवश्यक है। मिट्टी और उर्वरक वितरण के प्रबंधन के लिए ज्ञान-गहन दृष्टिकोण चारा उत्पादन में परिणामों में काफ़ी सुधार कर सकते हैं।

पानी में घुलनशील उर्वरक पौधों के लिए बेहतर पोषक तत्वों की पेशकश करके एक आशाजनक समाधान प्रदान करते हैं। ये उर्वरक पूरी तरह से पानी में घुलनशील होते हैं और एक कम नमक सूचकांक होता है, जिससे उन्हें पर्ण स्प्रे के रूप में या सिंचाई के माध्यम से आवेदन करना आसान हो जाता है। विभिन्न एनपीके योगों (जैसे, 19-19-19) में उपलब्ध, पानी में घुलनशील उर्वरकों में सल्फर और जस्ता जैसे द्वितीयक पोषक तत्व भी होते हैं। वे यह सुनिश्चित करते हैं कि पोषक तत्व पर्यावरणीय कारकों जैसे लीचिंग, कटाव या वाष्पीकरण से प्रभावित बिना फसलों के लिए उपलब्ध रहें।

पानी में घुलनशील उर्वरक पोषक तत्वों की अपव्यय को रोककर पोषक तत्वों के उपयोग दक्षता में सुधार करते हैं। उदाहरण के लिए, अनुशंसित उर्वरक खुराक के लगभग 25-30% को पानी में घुलनशील उर्वरकों के माध्यम से बचाया जा सकता है, किसानों के लिए इनपुट लागत को कम करते हुए, इनपुट लागत को कम करते हुए। ये उर्वरक मिट्टी में नमक संचय में योगदान नहीं करते हैं, लंबी अवधि में मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रखते हैं। पानी में घुलनशील उर्वरकों का उपयोग विभिन्न प्रकार के क्षेत्र की स्थितियों में किया जा सकता है और एक कुशल, संतुलित पोषक आपूर्ति प्रदान करता है, जिससे उच्च चारा पैदावार और चारा की पोषण गुणवत्ता में सुधार होता है।

जबकि पानी में घुलनशील उर्वरक कई लाभ प्रदान करते हैं, पोषक तत्व अधिभार का ख़तरा होता है यदि वे ओवरएप्ड या अनुचित रूप से पतला होते हैं, जिसके परिणामस्वरूप फाइटोटॉक्सिक चोट (पौधे की क्षति) हो सकती है। यह सही खुराक और अनुप्रयोग तकनीकों को सुनिश्चित करने के लिए सावधानीपूर्वक निगरानी और प्रबंधन की आवश्यकता को रेखांकित करता है। कृषी विगण केंद्र, बरनाला द्वारा किए गए फील्ड ट्रायल ने मक्का चारा उत्पादन में पानी में घुलनशील उर्वरकों (एनपीके 19-19-19) की प्रभावशीलता का आकलन किया। अध्ययन ने तीन उर्वरक प्रबंधन प्रथाओं की तुलना की: किसान का अभ्यास, उर्वरक की खुराक (आरडीएफ) और पानी में घुलनशील उर्वरकों पर फोलियर अनुप्रयोग।

परीक्षणों से पता चला कि 75% आरडीएफ के साथ संयुक्त, 1% एकाग्रता में पानी में घुलनशील

उर्वरकों के पर्ण आवेदन, मक्का के पौधे की वृद्धि (ताजा और शुष्क वजन) और हरे रंग की चारा की उपज में काफ़ी वृद्धि हुई है। पारंपरिक प्रथाओं की तुलना में चारे की पोषण गुणवत्ता में भी सुधार हुआ।

पानी में घुलनशील उर्वरक लीचिंग को कम करते हैं, प्रमुख पोषक तत्वों (एन, पी, के) और नाइट्रोजन वाष्पशीलकरण के अपवाह हानि को कम करते हैं, जो कम उत्पादन लागत में अनुवाद करता है और पर्यावरणीय प्रभाव को कम करता है।

कम पोषक तत्व अपव्यय और बेहतर दक्षता के परिणामस्वरूप किसानों के लिए कम वित्तीय बोझ में, विशेष रूप से उर्वरक लागत के मामले में। इज़राइल, जो अपने जल-कुशल कृषि प्रथाओं के लिए जाना जाता है, ने उर्वरक के उपयोग को उर्वरक के उपयोग का उपयोग किया है, जो उर्वरक आवेदन के साथ सिंचाई को एकीकृत करता है। पानी में घुलनशील उर्वरकों को सिंचाई के पानी में भंग कर दिया जाता है और ड्रिप सिंचाई प्रणालियों के माध्यम से सीधे रूट ज़ोन तक पहुँचाया जाता है।

ऑस्ट्रेलियाई किसान एक संतुलित पोषक तत्व प्रोफ़ाइल प्राप्त करने के लिए जैविक और धीमी गति से रिलीज़ उर्वरकों के साथ पानी में घुलनशील उर्वरकों के उपयोग को जोड़ते हैं। जापान नियंत्रित-रिलीज़ पानी में घुलनशील उर्वरकों को विकसित करने में सबसे आगे रहा है, जो पोषक तत्वों को धीरे-धीरे लंबी अवधि में जारी करने की अनुमति देते हैं। यूरोप में, विशेष रूप से नीदरलैंड जैसे देशों में, स्थायी कृषि प्रमाणन योजनाएँ पर्यावरण के अनुकूल खेती प्रथाओं के साथ संयोजन में पानी में घुलनशील उर्वरकों के उपयोग को प्रोत्साहित करती हैं।

किसानों को पानी में घुलनशील उर्वरकों के लाभों और उचित आवेदन के तरीकों के बारे में शिक्षित करने की आवश्यकता है। मिट्टी के परीक्षण और पोषक तत्वों की मानचित्रण जैसी सटीक खेती तकनीकों को पानी में घुलनशील उर्वरकों के उपयोग के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित करता है कि पोषक तत्व प्रबंधन विशिष्ट क्षेत्र की स्थितियों के अनुरूप है, अपव्यय को कम करता है और फ़सल प्रतिक्रियाओं में सुधार करता है। चल रहे शोध को नए जल-घुलनशील उर्वरकों के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो विभिन्न फसलों और पर्यावरणीय परिस्थितियों को पूरा करते हैं।

जल-घुलनशील उर्वरकों जैसे पर्यावरण के अनुकूल और कुशल उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा देने वाली नीतियों और सब्सिडी को मज़बूत किया जाना चाहिए। जल-घुलनशील उर्वरकों को अन्य टिकाऊ कृषि पद्धतियों, जैसे फ़सल चक्रण, कार्बनिक पदार्थ समावेशन और जल प्रबंधन तकनीकों के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए। जल-घुलनशील उर्वरक मक्का चारा उत्पादन में पारंपरिक उर्वरकों के लिए एक टिकाऊ और कुशल विकल्प का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे उर्वरक उपयोग दक्षता में सुधार करते हैं, मिट्टी के स्वास्थ्य को बहाल करते हैं और गुणवत्ता से समझौता किए बिना उच्च चारा उपज सुनिश्चित करते हैं।

जल-घुलनशील उर्वरक एक संतुलित, पर्यावरण के अनुकूल और लागत प्रभावी दृष्टिकोण प्रदान करते हैं जो पर्यावरणीय जोखिमों को कम करते हुए किसानों को कृषि उत्पादकता बनाए रखने में मदद कर सकते है।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095. newstransportvishesh@gmail.com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। RNI No :- DELHIN/2023/86499. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023